

सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच



वर्ष- 18 अंक - 31 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शनिवार 14 नवम्बर 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

सार-संक्षेप

जनजातीय गौरव दिवस पर कल जनजातीय संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क

रायपुर। जनजातीय गौरव दिवस 2026 के अवसर पर आगामी 15 नवंबर 2026 को नवा रायपुर स्थित दोनों प्रमुख जनजातीय संग्रहालयों में आम नागरिकों और पर्यटकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संस्थान परिसर में स्थित शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय और छत्तीसगढ़ जनजातीय संग्रहालय में रविवार को किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।

आईफोन के लिए फर्जी सिविल-जज बनकर दोस्त को ही ठगा

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक युवती ने अपनी ही बचपन की सहेली को ठगकर 1.88 लाख रुपए ऐंठ लिए। आरोप है कि उसने खुद को सुप्रीम कोर्ट की वकील और राजस्थान कैडर की चयनित सिविल जज बताया। सहेली के भाई का पारिवारिक विवाद सुलझाने के नाम पर कभी पुलिस अधिकारी को पैसे देने तो कभी बड़े वकील की फीस के नाम पर रकम मांगी। पीड़िता का आरोप है कि 16 सितंबर को उससे पैसे लेने के बाद आरोपी नया आई फोन खरीदकर लाई और उसे दिखाया भी। जब उसे ठगी का शक हुआ और उसने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने गाली-गलौज कर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। मामले में खमतराई पुलिस ने पूजा सिंह उर्फ मीठी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

मथुरा में एक्सप्रेस-वे पर चलती बस में आग लगी

मथुरा। यमुना एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार-शनिवार दरमियानी रात डेढ़ बजे चलती डबल डेकर एसी बस में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस से 20 फीट ऊंची लपटें उठने लगीं। समय रहते बस में सवार सभी 40 यात्रियों ने भागकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक बस और उसमें रखा पूरा सामान पूरी तरह जल चुका था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बस की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। खजुराहो ट्रैवल्स की बस दिल्ली से मध्य प्रदेश के छतरपुर जा रही थी।

राजनांदगांव में 23 एकड़ जमीन की लीज कैंसिल, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

राजनांदगांव। बसंतपुर में 23 एकड़ के भूखंड की लीज निरस्त करने के बाद प्रशासन ने निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार सुबह राजस्व अमला बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा। एसडीएम गौतम पाटिल, तहसीलदार पीएल नाग और पुलिस की मौजूदगी में निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। कलेक्टर जितेंदर यादव ने इस भूखंड की लीज निरस्त की थी। जानकारी के अनुसार 1944 में कुष्ठ रोगियों के लिए मिशनरी संस्था को रियासतकाल में 23 एकड़ का भूखंड आबंटित किया गया था। विगत तीन दशक से इसे लेप्रोसी सेंटर संचालित कर रहा था। प्रशासन ने नोटिस देने के बाद यहां निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है। राजस्व अमला लगातार मौके पर मौजूद है और अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है।

बंगाल की खाड़ी में फिर मंडरा रहा चक्रवाती तूफान का खतरा... ओडिशा और आंध्र में अलर्ट

नईदिल्ली। अंडमान सागर में बने नए कम दबाव के क्षेत्र से एक बार फिर चक्रवाती तूफान 'अकवान' का खतरा मंडराने लगा है, जिससे ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बारिश व तेज हवाओं के आसार हैं। दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जारी बर्फबारी के असर से मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में ठंड और सुबह की धुंध बढ़ गई है, जबकि राजस्थान के लिए आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

इसरो के INSAT-xDS सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों में अंडमान सागर के ऊपर घने बादलों की तेज गतिविधियां कैद हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार, मध्य अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। 15 नवंबर तक इसके डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है। 16 नवंबर की शाम तक यह मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है।



अक्टूबर में आ चुके हैं दो तूफान

बंगाल की खाड़ी में बन रहे इस संभावित तीसरे चक्रवात के चलते ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में एक बार फिर बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। समुद्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में महज एक हफ्ते के भीतर दो चक्रवाती तूफान- 'अर्नब' और 'मुरासु'- आंध्र प्रदेश के तट से टकरा चुके हैं, जिससे तटीय इलाकों में भारी बारिश और नुकसान हुआ था।

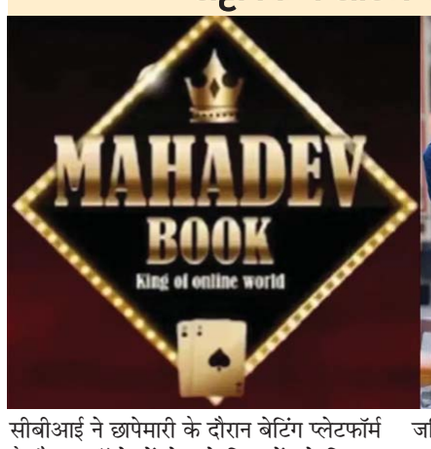
महादेव सट्टा ऐप केस में एक्शन : रायपुर-भिलाई सहित छह राज्यों के 33 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाल के दिनों में छह राज्यों में छापेमारी की है। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में इस मामले में कई अहम खुलासे हुए हैं, जिनके आधार पर विभिन्न राज्यों में छापेमारी की गई है। सीबीआई की यह छापेमारी अमृतसर, दिल्ली, नागौर, धौलपुर, भोपाल, रायपुर, दुर्ग, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई और नागपुर में की गई।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की टीमों ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले की जांच के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों में छह राज्यों के 33 ठिकानों पर छापेमारी की है। अधिकारियों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इनसे बेटिंग ऐप के लेनदेन में म्यूल बैंक खातों (दूसरों के नाम पर इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक खाते) और हवाला नेटवर्क के इस्तेमाल के संकेत मिले हैं।

सट्टा किंग सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के बाद हुए अहम खुलासे





सीबीआई ने छापेमारी के दौरान बेटिंग प्लेटफॉर्म के पैनल ऑपरेटरों से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। सीबीआई के प्रवक्ता के मुताबिक, कई जगहों पर लाइव बेटिंग और जुए के पैनल चलते हुए मिले, जिन्हें बाद में बंद करा दिया गया। सीबीआई अधिकारियों ने बताया, 'अब तक की जांच में सामने आया है कि यह प्लेटफॉर्म विदेश से एक मुख्य कार्यालय के जरिए चलाया जाता है, जबकि भारत में इसका कामकाज पैनल ऑपरेटरों के जरिए होता है। ये ऑपरेटर ग्राहकों की आईडी संभालते हैं और बेटिंग से मिलने वाली रकम ऐसे बैंक खातों में जमा कराते हैं, जिन्हें खास तौर पर दूसरे लोगों के नाम पर खोला या किराये पर लिया जाता है। इसके बाद मुनाफे की रकम हवाला के जरिए विदेश भेजी जाती है।

सामने आई कई जानकारियां

सीबीआई ने बताया कि यह कार्रवाई ऐप के प्रमुख प्रमोटरों में से एक सौरभ चंद्राकर से मिली जानकारी के आधार पर की गई। चंद्राकर को ओमान से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद सीबीआई ने एक नवंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने पूछताछ के लिए उसे आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अधिकारियों के अनुसार, चंद्राकर से पूछताछ में अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म के कामकाज और पूरे देश में फैले उसके पैनल ऑपरेटरों के नेटवर्क से जुड़ी कई जानकारियां सामने आईं। जांचकर्ताओं ने पूछताछ के दौरान उसके सामने जांच में जुटाए गए दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी रखे। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने महादेव ऑनलाइन बुक मामले में दो एफआईआर दर्ज की हैं।

छोटे भाई की पत्नी की हत्या के बाद शव को भून खाने लगा आरोपी

सरायकेला। झारखंड में सरायकेला-खरसावां जिले में कुचाई के जंबरो गांव में रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है। 47 वर्षीय आदिवासी महिला विश्वासी सोय की कथित तौर पर धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई। आरोपी पर हत्या के बाद महिला के अंगों के साथ अमानवीय क्रूरता करने और उन्हें पकाने के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम गांव में एक स्थानीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। विश्वासी सोय ने वहां पारंपरिक पेय 'हड़िया'का स्टॉल लगाया था। आरोप है कि गांव के ही 54 वर्षीय पैलेस मुंडा ने वहां हड़िया पी और महिला को अपने घर ले गया। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटीं, तो उनके पति निर्मल सोय उनकी तलाश में निकले। रात 12 बजे घर के पास महिला का शव बरामद हुआ। इस दृश्य को देख परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मृतका के पति ने आरोप लगाया है कि पैलेस मुंडा ने हत्या के बाद शव के साथ बेहद क्रूरता की। आरोपी ने मृतका के शरीर के कई हिस्सों (जांघ, कलेजी और निजी अंगों) को काट लिया और घर के पीछे कढ़ाई में भूनकर खाने की कोशिश कर रहा था। घटना की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पैलेस मुंडा को पकड़ लिया और कुचाई पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

एंबुलेंस ट्रक में घुसी, दो महिलाओं की मौत

श्रीकंचनपथ न्यूज

महासमुंद। शनिवार सुबह बागबाहरा के समीप नेशनल हाईवे 353 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। मरीज को लेकर ओडिशा की ओर जा रही एक एंबुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एंबुलेंस में सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एंबुलेंस महासमुंद अस्पताल से मरीज को लेकर ओडिशा की ओर जा रही थी। इसी दौरान बागबाहरा के पास वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसा। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना में दो महिलाओं की जान चली गई, तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस दुर्घटना के कारणों और मृतकों एवं घायलों की पहचान सहित अन्य जानकारी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद एंबुलेंस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी चालक की तलाश जारी है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने की शिष्टाचार भेंट



श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह तथा देश के अन्य प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों ने 11 नवम्बर 2026 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में सौजन्य भेंट की। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह द्वारा प्रदेश के बस्तर संभाग में पिछले वर्ष सम्पन्न हुए स्थानीय निकायों के शांतिपूर्ण चुनावों में आई चुनौतियों व आयोग द्वारा अपनाई गई रणनीति से संबंधित एक बुकलेट की प्रति भी राष्ट्रपति कार्यालय को भेंट की गई।

खेल-खेल में बच्चे ने खा लिया पॉपपॉप पटाखे का पैकेट, मुंह में फटने से मासूम की मौत

श्रीकंचनपथ न्यूज

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले में दिवाली के दौरान पटाखा मुंह में फटने से दो साल के मासूम की मौत हो गई। घटना दीपावली के दूसरे दिन यानी 9 नवंबर की है। मासूम ने खेल खेल में पॉपपॉप यानी लहसून पटाखे का पैकेट खा लिया जो कि मुंह में भी फट गया। इससे मामूम को गंभीर चोट आई। परिजनों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। 11 नवंबर को मासूम ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक घटना 9 नवंबर की सुबह सीतापुर थाना क्षेत्र के नवापारा गांव में हुई थी। दीपावली के मौके पर आसपास के बच्चे पॉप-पॉप पटाखे फोड़ रहे थे। इसी दौरान दो वर्षीय आदित्य ने जमीन पर पड़ा एक छोटा पैकेट उठाकर मुंह में रख लिया। लहसून पटाखा बच्चे के मुंह में ही फट गया। इसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगा। बच्चे के पिता इंद्रजीत मांझी व परिजन उसे सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे। खून बहना बंद होने पर वे उसे घर ले आए। अगले दिन फिर से रक्तस्राव शुरू हुआ तो उसे अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद 11 नवंबर की दोपहर अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसी रात उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को बच्चे के गले के अंदर पटाखे के अवशेष भी मिले हैं।

सेल में पदोन्नति परीक्षा रद्द, केवल पुराने अभ्यर्थी दे सकेंगे एग्जाम

भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने गैर-कार्यकारी से कार्यकारी (जेएम-2026) कैडर में पदोन्नति के लिए 5 जुलाई को आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर दिया है। देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ियों और धांधली की शिकायतें मिलने के बाद प्रबंधन ने यह बड़ा कदम उठाया है। कॉरपोरेट कार्यालय ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आधिकारिक आदेश जारी किया है। ऑनलाइन परीक्षा होने के तुरंत बाद ही कई केंद्रों पर अनियमितताओं और धांधली के गंभीर आरोप लगे थे। जांच के बाद सतर्कता विभाग की रिपोर्ट में धांधली की पुष्टि होने के बाद प्रबंधन ने परीक्षा निरस्त की।

कोंडागांव में छात्राओं को योगाभ्यास के साथ मिला आत्मरक्षा का प्रशिक्षण

■ कोंडागांव के आयुष योग वेलनेस सेंटर में योग कार्यक्रम आयोजित

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के बस्तर प्रवास के दौरान कोंडागांव स्थित आयुष योग वेलनेस सेंटर में छात्राओं एवं युवतियों के लिए योगाभ्यास एवं आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में सुबह बड़ी संख्या में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए सामूहिक योगाभ्यास किया तथा योग के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभों की जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने छात्राओं को नियमित रूप से योग अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच विकसित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने युवतियों को योग के साथ-साथ आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज के समय में बेटियों का शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होना बेहद आवश्यक है। योग एवं मार्शल आर्ट जैसे प्रशिक्षण के माध्यम से युवतियां आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन सकती हैं। इससे वे न केवल अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होंगी, बल्कि भविष्य में समाज और प्रदेश का नाम भी रोशन कर सकेंगी।



कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ योग आयोग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं, योग प्रशिक्षण की संभावनाओं तथा छात्राओं एवं युवतियों को इन योजनाओं के माध्यम से मिलने वाले लाभों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें योग एवं आत्मरक्षा के प्रशिक्षण से जुड़कर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में डॉ. दुर्गा साहू, योग प्रशिक्षिका पूजा साहू, मार्सल आर्ट प्रशिक्षिका चंचल डिकसेना, देवीलाल पटेल एवं अरुण कुमार साह उपस्थित रहे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ योग आयोग के मीडिया प्रभारी सीमांत कश्यप भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। योग, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के माध्यम से बेटियों को सशक्त बनाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज और प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य रहा।



संपादकीय

फिर दहशत की दस्तक

कश्मीर में सुरक्षा चूक की गुंजाइश नहीं

भारत विरोध को प्राणवायु बनाने वाले पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह भारत पर घात का कोई मौका चूकेगा। पाक प्रायोजित आतंक का चेहरा एक बार फिर जम्मू-कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमले में उजागर हुआ है। किश्तवाड़ में दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों यानी एसपीओ की हत्या और कुलगाम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की पोस्ट पर हमले की हालिया घटनाएं चिंता बढ़ाने वाली हैं। करीब चौबीस घंटे के भीतर हुई ये घटनाएं बताती हैं कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा हालात अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं। ये घटनाएं एक बार फिर याद दिलाती हैं कि सामान्य स्थिति और स्थायी शांति के दावों से इतर इलाके में आतंकवाद के रक्तबीज मौजूद हैं। दुखद ही है कि लापता होने के एक दिन बाद दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों के गोलियों से छलनी शव बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सीआरपीएफ की चेकपोस्ट पर हुए हमले में तीन जवान घायल हुए हैं। निस्संदेह,यह हमारी खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों के लिये नई चुनौती है। उल्लेखनीय है कि इससे ठीक एक साल पहले राजधानी में लाल किले के पास एक कार धमाके में ग्यारह लोगों की जान चली गई थी। कालांतर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनएआई की व्यापक जांच के बाद पता चला था कि विस्फोट की घटना में जम्मू-कश्मीर स्थित पुलवामा के एक डॉक्टर की मुख्य भूमिका रही थी। बहरहाल, जम्मू-कश्मीर में हालिया आतंकी हमलों की सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार के उस दावे पर सवाल उठाये हैं, जिसमें कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर आतंकवाद से मुक्त हो चुका है। ऐसे वक्त बयानबाजी से आगे बढ़कर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को प्रभावी बनाने, सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि स्थानीय समुदायों की चिंता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

> “ ये घटनाएं एक बार फिर याद दिलाती हैं कि सामान्य स्थिति और स्थायी शांति के दावों से इतर इलाके में आतंकवाद के रक्तबीज मौजूद हैं। दुखद ही है कि लापता होने के एक दिन बाद दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों के गोलियों से छलनी शव बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सीआरपीएफकी चेकपोस्ट पर हुए हमले में तीन जवान घायल हुए हैं। निस्संदेह,यह हमारी खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों के लिये नई चुनौती है। उल्लेखनीय है कि इससे ठीक एक साल पहले राजधानी में लाल किले के पास एक कार धमाके में ग्यारह लोगों की जान चली गई थी।

निस्संदेह, आज के आधुनिक उन्नत तकनीक के युग में आतंकवाद से लड़ाई के लिये तमाम विकल्प सुरक्षा बलों के पास मौजूद हैं। लेकिन स्थानीय समाज में घुल-मिल कर रहने वाले आर्तकियों तक पहुंच बनाने के लिये लोकल संपर्क सूत्रों की बड़ी भूमिका होती है। कोई भी केंद्रीय सत्ता स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने में असहजता महसूस करेगी। पाकिस्तानी सीमा से लगने वाले दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे बिना किसी भय व दबाव के सुरक्षा एजेंसियों से सहयोग करें। निस्संदेह, आतंकवाद को हराने के लिये उनकी सुरक्षा, उनका भरोसा और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाये रखने के लिये कानून-व्यवस्था व शांति बनाये रखना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने देखा था कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद घाटी की आर्थिकी को भारी चोट पहुंची थी। जो अब धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगी थी। देश के विभिन्न भागों व विदेशों से आने वाले पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने लौटने लगे थे। निर्विवाद रूप से किश्तवाड़ जैसे इलाकों में पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। लेकिन गाहे-बगाहे होने वाले आतंकी हमले व हिंसा पर्यटकों को दूर रख सकती है। इससे विकास की गति बाधित होती है और स्थानीय लोगों की आजीविका संकट में पड़ जाती है। भले ही अभी तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिल पाया हो, लेकिन इसके बावजूद घाटी के लोगों का भरोसा हासिल करना बेहद जरूरी है। खासकर स्थानीय लोगों को सीमा पार से पोषित आतंकवाद के खात्मे के साथ कानून-व्यवस्था में भरोसा दिलाना जरूरी है। इस केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों से निपटने और जनता का भरोसा फिर से बहाल करने के लिये ठोस और कारगर रणनीति की जरूरत है। इसमें दो राय नहीं कि सीमाओं की सुरक्षा करने और घुसपैठ को रोकने में सेना व सुरक्षा बलों ने काफी हद तक सफलता पायी है, लेकिन स्थानीय समाज में घुसपैठ करने वाले आतंकियों से निबटना अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

कैंसर की दवाओं को सस्ती बनाने की प्रक्रिया और मरीजों को प्राथमिकता



जगत प्रकाश नड्डा

'कैंसर' शब्द पल भर में ही किसी परिवार की जिंदगी बदल देता है। इस बीमारी की पहचान होने के बाद, मरीजों व उनके परिजनों को इलाज, आर्थिक मामलों और भविष्य से जुड़े कई कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कई परिवारों के लिए तो दवाओं का खर्च एक ऐसे समय में अतिरिक्त बोझ बन जाता है, जब सारे संसाधन मरीज को स्वस्थ करने में लगाए जाने चाहिए। एक करुणामयी स्वास्थ्य प्रणाली को सिर्फ बीमारी ही नहीं, बल्कि उससे पैदा होने वाली आर्थिक तंगी का भी समाधान निकालना चाहिए।

इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने कैंसर के इलाज को और अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाकर 137 चिन्हित गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं के 'ट्रेड मार्जिन' को तर्कसंगत बना दिया है। इस उपाय के तहत, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 'ट्रेड मार्जिन' को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है और ये संशोधित कीमतें 9 नवंबर, 2026 से लागू हो गई हैं। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है: मरीज द्वारा चुकायी जाने वाली कीमत में अत्यधिक 'मार्क-अप' के बजाय वितरण संबंधी मार्जिन का उचित व तर्कसंगत समावेश होना चाहिए।

इस कदम के नतीजे दवा की दुकानों पर साफ नजर आने लगे हैं। कुल 80 से अधिक दवा कंपनियों ने 137 में से 121 दवाओं से जुड़े 1,366 उत्पादों के लिए संशोधित एमआरपी की सूचना दी है। इनमें से प्रत्येक 5 में से 4 से अधिक उत्पादों की कीमतें कम हो गई हैं। इन दवाओं में से लगभग आधे की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है और कुछ दवाएं तो अब पहले की तुलना में 96 प्रतिशत से भी कम कीमत पर मिल रही हैं। कीमोथेरेपी के कई दौर का खर्च उठाने वाले परिवार के लिए, इस कदम से इलाज के मासिक बिलों में काफी अंतर आ जाता है। पिछले वर्ष की खपत के आधार पर, मरीजों एवं उनके परिवारों को प्रत्येक वर्ष लगभग 3,500 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है। यह वो रकम है जो अत्यधिक 'ट्रेड मार्जिन' में खप जाने के बजाय उनके घरेलू बजट में ही बनी रहेगी।

यह निर्णय पिछले अनुभवों के आधार पर लिया गया है। वर्ष 2019 में, एनपीपीए ने 'ट्रेड मार्जिन के युक्तिकरण' (टीएमआर) की कवायद के तहत एक प्रायोगिक कार्यक्रम चलाया था जिसमें कैंसर की गैर-अनुसूचित श्रेणी की 42 दवाएं शामिल थीं। इससे 526 ब्रांडों की एमआरपी में 90 प्रतिशत तक की कमी आई थी। अब इसी प्रक्रिया को 137 दवाओं की एक बड़ी सूची तक बढ़ाया जा रहा है। इन दवाओं की पहचान एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई है। इस विशेषज्ञ समिति में प्रमुख कैंसर विशेषज्ञ (ऑन्कोलॉजिस्ट), चिकित्सा विशेषज्ञ, अस्पताल विशेषज्ञ और सरकारी प्रतिनिधि शामिल थे। इस सूची को समय-समय पर अद्यतन किया जाता रहेगा।

एक न्यायसंगत स्वास्थ्य व्यवस्था में दवाओं का किफायती होना जरूरी है। खासकर, भारत जैसे देश में। बाजार में उपलब्ध होने के बावजूद अगर किसी दवा को बहुत महंगी होने के कारण खरीदना संभव न हो पाए, तो वह मरीज के किसी काम की नहीं है। एनपीपीए 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' के तहत जारी 'औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), 2013' के जरिए दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है। जहां वह 'आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची' में शामिल जरूरी दवाओं की अधिकतम कीमतें (सीलिंग प्राइस) निर्धारित करता है, वहीं गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों में हर वर्ष होने वाली बढ़ोतरी पर नजर भी रखता है। हालांकि, बाजार के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कुछ गैर-अनुसूचित दवाओं के मामले में फैक्ट्री से निकलने वाली कीमत और ग्राहक द्वारा चुकाई गई कीमत के बीच का अंतर बहुत अधिक था। इनमें कैंसर की वैसी दवाएं भी शामिल थीं, जिनकी खुराकें इलाज के दौरान अक्सर कई बार और बार-बार लेने की जरूरत पड़ती है। व्यापार श्रृंखला (ट्रेड चैनल) में बहुत अधिक मार्जिन और इलाज के भारी खर्च को देखते हुए, सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए कदम उठाया है और मार्जिन को एमआरपी के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है।

सरकार इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी ध्यान दे रही है ताकि मरीजों और उनके परिजनों को टीएमआर का पूरा लाभ मिल सके। निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि संशोधित कीमतें हर फार्मेसी और अस्पताल तक पहुंचें। साथ ही, सभी फार्मेसियों और अस्पतालों को इन कीमतों को पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित करना होगा और इनका सख्ती से पालन करना होगा। मरीज और उनकी देखभाल करने वाले लोग एनपीपीए की वेबसाइट और 'फार्मा सही दाम' ऐप पर इन संशोधित कीमतों को देख सकते हैं। अगर कोई फार्मेसी या अस्पताल निर्धारित कीमत से अधिक पैसे वसूलता है, तो वे इसकी शिकायत सरकार से कर सकते हैं।

टीएमआर की प्रक्रिया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों से चल रहे स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यापक बदलाव का एक हिस्सा है। इस सरकार ने स्वास्थ्य को केवल कुछ चुनिंदा लोगों के विशेषाधिकार के रूप में नहीं, बल्कि गरिमा, उत्पादकता और सामाजिक न्याय की नींव के रूप में देखा है। खासकर, समाज के सबसे गरीब तबके के लिए। 'आयुष्मान भारत' ने कमजोर परिवारों के लिए अस्पताल की सुविधाओं की सुलभता को आसान बना दिया है। सरकार ने कैंसर की रोकथाम, शुरुआती पहचान और समय पर इलाज के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत 'गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' (एनपी-एनसीडी) के तहत, 500 से अधिक 'डे-केयर कैंसर सेंटर' स्थापित किए गए हैं ताकि कीमोथेरेपी तथा कैंसर संबंधी अन्य डे-केयर सेवाएं समय पर मिल सकें। 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए कैंसर की आम बीमारियों की मुफ्त जांच की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे कैंसर का शुरुआती चरण में ही पता चल जाता है।

तृतीयक स्तर की देखभाल (टर्शियरी केयर) को मजबूत करने हेतु, टाटा मेमोरियल सेंटर ने कैंसर की व्यापक देखभाल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाराणसी, विशाखापत्तनम, न्यू चंडीगढ़, गुवाहाटी, संगरूर और मुजफ्फरपुर में छह अस्पताल स्थापित किए हैं। इसके अलावा, सभी 22 नए एम्स में भी जांच, चिकित्सा और सर्जरी की सुविधाएं सहित कैंसर उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

'प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना' किफायती दामों पर अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। सरकार ने जीवन रक्षक एवं आवश्यक दवाओं को 50 से 90 प्रतिशत तक की छूट पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'अमृत' ऊर्मेसियां भी स्थापित की हैं। इलाज के खर्च को और कम करने के इरादे से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और पुरानी बीमारियों से जुड़ी 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क (बेसिक कस्टम ड्यूटी) से पूरी तरह छूट दी गई है। कैंसर-रोधी दवाओं के 'ट्रेड मार्जिन' को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया किफायती दवाएं उपलब्ध कराने की इसी व्यापक प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाती है।

उतना ही महत्वपूर्ण बात यह है कि टीएमआर की प्रक्रिया इस तथ्य को रेखांकित करती है कि दवाओं का किफायती होना और फार्मास्यूटिकल उद्योग का स्वस्थ रूप से आगे बढ़ना, दोनों ही साथ-साथ चलने चाहिए। भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा और दवाओं के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में हमारी हैसियत में बराबर का हिस्सेदार है। यह सीमा (कैप) व्यापार श्रृंखला के मार्जिन पर लागू होती है, जबकि दवा निर्माताओं की बिक्री कीमत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह, दवा निर्माताओं की वैध कमाई सुरक्षित रहती है। साथ ही अनुसंधान, विकास और नवाचार की प्रक्रिया में निवेश करते रहने की उनकी क्षमता भी बनी रहती है।

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, हम एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली बनाने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे जो मरीजों की सुरक्षा करे, नवाचार का सम्मान करे, जिम्मेदार उद्योग को समर्थन प्रदान करे और मानवीय गरिमा को केन्द्र में रखे। किसी देश के स्वास्थ्य तंत्र की सफलता को सिर्फ चिकित्सा तकनीक में हुई प्रगति के आधार नहीं, बल्कि वहां के लोगों को जरूरत के समय इन सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर ही आंका जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा के कई पहलू होते हैं, लेकिन इसके केन्द्र में हर नागरिक के लिए किफायती, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए। इस निर्णय के जरिए, सरकार ने एक सीधे एवं सरल सिद्धांत को फिर से दोहराया है: जीवन रक्षक दवाओं पर अत्यधिक मार्जिन होने के कारण किसी भी परिवार को ऐसी आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, जिसे टाला जा सकता था।

(लेखक केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं)

जनजातीय गौरव दिवस : जड़ों की ओर लौटने और इतिहास के महानायकों के पुण्य स्मरण का महापर्व



तिलका मांझी

तिलका मांझी

ताराशंकर सिन्हा
सहायक संचालक

15 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, एक संकल्प है जब भारत के इतिहास की बात होती है तो अक्सर दिल्ली के महलों, मुगलों के युद्धों और अंग्रेजों की चालों तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन भारत का असली इतिहास जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे लिखा गया है। वह इतिहास उन आदिवासियों ने लिखा है जिन्होंने कभी किताबों में अपना नाम नहीं मांगा, लेकिन अपनी मिट्टी के लिए प्राण दे दिए। उन्हीं वीरों को याद करने के लिए केन्द्र सरकार के आह्वान पर वर्ष 2021 से हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है।

धरती आबा बिरसा मुंडा से शुरू हुई यह यात्रा-

जनजातीय गौरव दिवस के लिए 15 नवंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1875 में वर्तमान झारखंड के उलिहातु गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ 25 साल जिए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी थीं। उन्होंने नारा दिया था – अबुआ दिशोम रे अबुआ राज यानी हमारे देश में हमारा ही राज होगा। अंग्रेजों ने उन पर जमींदारी, बेगार और धर्मांतरण का जो तंत्र थोपा था, उसके खिलाफ बिरसा ने उलगुलान यानी महाविद्रोह का बिगुल फूंका। आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं, धरती आबा कहते हैं। 2021 में जब केंद्र सरकार ने उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, तो ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये इतिहास के सच के साथ न्याय था। भुला दिए गए महानायक बिरसा मुंडा अकेले नहीं थे। भारत की आजादी की लड़ाई में आदिवासी समाज का योगदान सबसे बड़ा और सबसे कम दर्ज हुआ है। तिलका मांझी ने 1784 में ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जब 1857 की क्रांति का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। सिद्धो-कान्हो ने संथाल हूल का नेतृत्व किया। रानी गाइदिन्ल्यू मात्र 13 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गईं। अल्लूरी सीताराम राजू, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधूर, शहीद गैंद सिंह- ये नाम इतिहास की किताबों के हाशिये पर रह गए। जनजातीय गौरव दिवस इन सभी नामों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास है जो सिर्फ अतीत नहीं, वर्तमान भी है।

छत्तीसगढ़ को यूं ही आदिवासियों का प्रदेश नहीं कहा जाता है। यहां की 32 प्रतिशत से ज्यादा आबादी जनजातीय समाज की है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, जशपुर से लेकर कोरबा तक, इस प्रदेश की आत्मा आदिवासी संस्कृति में बसती है। इसलिए जब 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ के लिए यह सिर्फ एक शासकीय कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि अपनी पहचान का उत्सव होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले तीन वर्षों में आदिवासी अस्मिता, विकास और स्वाभिमान को पहचान दिलाने अनवरत प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ के अपने जनजातीय नायकों को सामने लाया। बिरसा मुंडा के साथ-साथ यहां शहीद वीर नारायण सिंह को याद किया जाता है। सोनाखान के इस वीर ने 1857 से पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। सरकार ने रायपुर में उनकी भव्य प्रतिमा, संग्रहालय और उनकी जयंती पर राज्य स्तरीय आयोजन शुरू किए। इसी तरह शहीद गुंडाधूर, शहीद गैंद सिंह, रानी दुर्गावती जैसे नायकों पर किताबें, नाटक और प्रदर्शनी आयोजित की जा रही हैं, ताकि बच्चे सिर्फ किताबों में ही नहीं, अपने गांव-शहर में इतिहास के वास्तविक नायकों के बारे में जान सकें।

छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश में आज भी करोड़ों आदिवासी भाई-बहन अपनी भाषा, बोली, पारम्परिक नृत्य, पुरखों से पूजे जा रहे देवी-देवता, अपनी खेती को बचाए हुए हैं। बस्तर का पंडुम, सरगुजा का करमा नृत्य, जशपुर का सुआ नृत्य सिर्फ लोक मनोरंजन नहीं हैं, ये हजारों साल पुरानी सभ्यता की जीवित धरोहर हैं। जनजातीय गौरव दिवस हमें यह सिखाता है कि विकास का मतलब आदिवासी को शहर जैसा बनाना नहीं है, बल्कि आदिवासी की पहचान को बचाते हुए उसे आगे बढ़ाना है।

जनजातीय गौरव दिवस की असली श्रद्धांजलि तब होगी जब आदिवासी बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा का मौका दें। उनके जल, जंगल, जमीन के अधिकारों का सम्मान करें। उनके उत्पादों- महुआ, तेंदूपत्ता, बांस शिल्प, लौह शिल्प को समुचित बाजार दें। उन्हें पिछड़ा न कहकर, भारत का मूल निवासी और गौरव कहें। इतिहास गवाह है कि जिस देश ने अपने जंगल के बेटों को भुला दिया, वो अपनी वास्तविक जड़ों से कोसों दूर हो गया। इसलिए 15 नवंबर को सिर्फ बिरसा मुंडा को याद नहीं करना है, बल्कि यह संकल्प दोहराना है कि हम आदिवासी गौरव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि जब तक आदिवासी गौरवान्वित नहीं होगा, तब तक भारत गौरवान्वित नहीं हो सकता।

पीएम जनमन योजना से कमार जनजाति का जीवन हुआ खुशहाल

ताराशंकर सिन्हा, कमलेश साहू
सहायक संचालक, जनसंपर्क

केंद्र एवं राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली पीएम जनमन योजना (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) से कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखण्ड के विशेष पिछड़ी कमार जनजाति परिवारों के जीवन में बदलाव की नई तस्वीर उभर रही है। कभी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में खानाबदोश सा जीवन यापन करने वाले इन परिवारों तक अब पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और संचार जैसी सुविधाएं पहुंच रही हैं। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर कमार जनजाति के परिवार विकास की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं तथा बेहतर और सम्मानजनक जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम मावलीपारा, बिहावापारा, मारवाड़ी, धनोरा, सांईमुण्डा, मुसुरपुट्टा, दुधावा, बासनवाही, गंवरसिल्ली, भैंसमुण्डी, दलदली, बादल और डोमपदर सहित 13 ग्रामों में कमार जनजाति के 79 परिवार निवासरत हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 304 है। पहले इन परिवारों की आजीविका मुख्य रूप से बांस शिल्प और मजदूरी पर निर्भर थी। सीमित संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बीच



जीवनयापन करने वाले इन परिवारों को अब पीएम जनमन मिशन के माध्यम से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पक्के आवास से साकार हो रहा सुरक्षित घर का सपना

पीएम जनमन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक 22 पक्के आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। इससे कमार जनजातीय परिवारों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध हुआ है। योजना से लाभान्वित होने वालों में ग्राम भैंसमुण्डी के इतवारूराम शोरी, मुसुरपुट्टा के पनकूराम मरकाम, सरजूराम मरकाम, प्रभुराम मरकाम, राजमन, राधुराम एवं सगराम शोरी, डोमपदर के मुकेश कुमार नेताम, दलदली की कमलाबाई कमार, भीमाडीह की सोनईबाई शोरी, मावलीपारा की देवलीबाई नेताम, मोतीलाल नेताम, लखनराम नेताम एवं अंजोरसिंह मरकाम, सांईमुण्डा के नवलसिंह शोरी, दुकाल नेताम एवं झनकीन नेताम, भीमाडीह के काशीराम मरकाम, सुकमन मरकाम एवं प्रेमबाई शोरी तथा बादल के देवेन सिंह कुंजाम एवं रेवती बाई शामिल हैं।



सड़क, बिजली, पेयजल और संचार सुविधाओं का विस्तार

कमार जनजातीय बाहुल्य इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। नल-जल योजना के माध्यम से घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। वहीं, सड़क निर्माण से गांवों की संपर्क व्यवस्था मजबूत हुई है। दलदली से कमारपारा दलदली, भीमापारा से बासनवाही के बाजारपारा, मावलीपारा के आवासपारा से कमारपारा तथा गंवरसिल्ली से खासपारा तक सड़क निर्माण कराया गया है। सभी ग्रामों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिससे बच्चों और महिलाओं को आंगनबाड़ी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। वन धन केंद्र सरोना एवं नरहरपुर से सभी 13 बसाहटें नजदीक हैं, जिससे जनजातीय परिवारों को वन आधारित आजीविका गतिविधियों से जुड़ने की सुविधा मिल रही है। सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा मोबाइल टॉवर नेटवर्क की उपलब्धता से ये बसाहटें संचार सुविधा से भी जुड़ गई हैं। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल और मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 09 केंद्रीय मंत्रालयों के समन्वय से 11 प्रमुख गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से पात्र परिवारों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कमार जनजाति के सदस्यों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन बैंक खाते, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक सुविधाओं से जोड़ा गया है। कमार जनजातीय परिवारों के 28 युवाओं को सरकारी नौकरी भी प्रदान की गई है। पीएम जनमन योजना के माध्यम से कमार जनजातीय परिवारों को आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के साथ-साथ उनकी आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। शासन की इन योजनाओं से अब दूरस्थ बसाहटों तक विकास की सुविधाएं पहुंच रही हैं। इससे विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के साथ उनके लिए आत्मनिर्भरता और बेहतर भविष्य की नई संभावनाएं भी बन रही हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

इबोला वायरस रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु मॉकड्रिल आयोजित

दुर्ग। विश्व स्तर पर इबोला वायरस रोग के प्रसार की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा इबोला वायरस रोग की रोकथाम, नियंत्रण एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया की तैयारियों का आकलन करने हेतु राज्य से डॉ. खेमराज सोनवानी, उप संचालक एवं राज्य सर्वलेंस अधिकारी, डॉ. माधवी एम्स रायपुर तथा डॉ. चयनिका राज्य एंटोमॉलॉजिस्ट की मौजूदगी में तथा जिले से डॉ. मनोज दानी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग के निर्देशन में डॉ सी.बी.एस. बंजारे, जिला सर्वलेंस अधिकारी, डॉ. अशीषन कुमार मिंज, सिविल सर्जन, डॉ. आलोक रामटेके, डॉ. आर. के. मल्होत्रा, डॉ. पुजा वर्मा, डॉ. अंकिता राउत, डॉ. उन्नयन साहू, डॉ. सौरीन चौटर्जी, मैट्रन, स्टाफ नर्स व अन्य स्टाफ के उपस्थिती में, जिला चिकित्सालय, दुर्ग में 12 नवंबर 2026 को मॉकड्रिल का सफ्ल आयोजन किया गया। उक्त मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य संदिग्ध इबोला मरीज की पहचान से लेकर उपचार, आइसोलेशन, नमूना संग्रहण एवं परिवहन तथा रिपोर्टिंग तक की संपूर्ण व्यवस्था का परीक्षण करना है। साथ ही आइसोलेशन सेंटर में इबोला संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्विपमेंट (पीपीई) विशेषकर इबोला-विशिष्ट पीपीई किट एवं अन्य आवश्यक सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

छठ महापर्व की तैयारियों का विधायक ललित चंद्राकर ने लिया जायजा

दुर्ग। सूर्योपासना के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने छठ पर्व के मद्देनजर मां कल्याणी शीतला मंदिर तालाब, मरोदा टैंक एवं नेवई डेम का निरीक्षण कर घाटों पर की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान विधायक ने छठ घाटों पर साफ-सफाई, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, अस्थायी शौचालय, बैरिकेडिंग, पार्किंग, आवागमन के मार्ग तथा सुरक्षा इंतजामों का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पर्व से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं, ताकि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि छठ महापर्व आस्था, श्रद्धा और अनुशासन का पर्व है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अस्ताचलगामी एवं उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से घाटों पर पानी की गुणवत्ता की जांच, गहरे पानी वाले स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाने, गोताखोरों एवं पुलिस बल की तैनाती तथा महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव को मिली स्वीकृति, महापौर परिषद ने दी मंजूरी

श्रीकंचनपथ न्यूज



भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं निगम आयुक्त सुरूचि सिंह की उपस्थिति में आहूत की गई।

बैठक में निगम के विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं, कर्मचारियों की उपलब्धता तथा शहर में बेहतर प्रशासनिक एवं मूलभूत सुविधाओं के संचालन को लेकर विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से वाहन शाखा के लिए अस्थायी श्रमिक उपलब्ध कराने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की नियुक्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों को विचारार्थ रखा गया। बैठक के प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निगम की वाहन शाखा में उच्च कुशल, कुशल एवं अर्द्धकुशल वाहन चालक तथा हेल्पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस कार्य के लिए कुल 1 करोड़ 77 लाख 54 हजार 790 रुपये की संभावित लागत निर्धारित की गई है। उक्त कार्य कराए जाने के संबंध में सलाहकार समिति द्वारा पूर्व में अनुशंसा प्रदान की जा चुकी है। समिति की अनुशंसा के पश्चात जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। महापौर परिषद के सदस्यों ने प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के पश्चात कार्य कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की। वाहन शाखा में आवश्यकतानुसार वाहन चालक एवं हेल्पर उपलब्ध होने से निगम के वाहनों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकेगा। इससे निगम के विभिन्न विभागों में संचालित वाहनों के कार्यों को गति मिलेगी तथा नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन में भी सहूलियत होगी।

वार्ड क्रमांक 33 संतोषी पारा शर्मा कॉलोनी में अधो संरचना मद वित्तीय वर्ष 2024-25 में डोम शेड निर्माण कार्य में बची हुई शेष राशि से वार्ड क्रमांक 33 संतोषी पारा कैंपेश्वर बैजनाथ धाम के पास डोम शेड निर्माण कार्य कराए जाने की अनुमति प्रदान की गई। इसी प्रकार बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के एक पद पर नियुक्ति के संबंध में भी चर्चा की गई।

कम उत्पादन होने पर भी किसानों को मिलेगी पूरी आदान सहायता

प्रति एकड़ 13,839 का निर्णय किसान हित में महत्वपूर्ण पहलः मंत्री गजेन्द्र यादव

श्रीकंचनपथ न्यूज



दुर्ग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में पात्र धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता देने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट मंत्री एवं दुर्ग विधायक गजेन्द्र यादव ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे प्रदेश के किसानों के हित में महत्वपूर्ण और राहतकारी पहल बताया है।

केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की मेहनत, उनकी जरूरतों और कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब किसान यदि कम उत्पादन के कारण प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं, तब भी उन्हें सत्यापित धान के रकबे के अनुसार पूरी निर्धारित आदान सहायता राशि मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पहले कम उत्पादन होने की स्थिति में किसानों को निर्धारित मात्रा के अनुपात में ही सहायता मिल पाती थी। अब सरकार ने किसानों को राहत देते हुए यह सुनिश्चित किया है कि कम उपज के कारण उन्हें आर्थिक सहायता से वंचित न होना पड़े। यह निर्णय विशेषकर उन किसानों के लिए लाभकारी होगा, जहां प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण धान का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान कल्याण की भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। धान खरीदी के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की निर्धारित दर और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है।

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, किसानों को नहीं होगी कोई परेशानी - ललित चंद्राकर

दुर्ग। प्रदेश में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी को लेकर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने अपने निवास कार्यालय में सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों एवं प्रबंधकों की आवश्यक बैठक ली। बैठक में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। विधायक श्री चंद्राकर ने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी खरीदी केन्द्रों में बारदाना, कांटा-बांट, नमी मापक यंत्र, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली-पानी, छाया एवं पेयजल की व्यवस्था समय से पहले सुनिश्चित की जाए। टोकन व्यवस्था पारदर्शी रखी जाए और धान का उठाव समय पर हो ताकि केन्द्रों पर जाम न लगे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व वाली सुशासन सरकार ने किसानों के पक्ष में बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। अब उपार्जन केंद्रों में 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्य बाध्यता समाप्त कर दी गई है। किसान अपनी जरूरत के अनुसार ही धान बेच सकेंगे। बेची गई मात्रा पर समर्थन मूल्य और 21 क्विंटल के दायरे में शेष बची उपज पर 'कृषक उन्नति योजना' के तहत अंतर राशि (बोनस) सीधे बैंक खाते में मिलेगी। यदि कोई किसान एक दाना भी धान नहीं बेचता है, तब भी वह डीसीएस सर्वे के आधार पर बोनस राशि पाने का पात्र होगा, इसके लिए केवल शपथ-पत्र देना होगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज रकबे के आधार पर किसानों को अधिकतम 13,839 रुपये प्रति एकड़ तक की आदान सहायता मिलेगी।

विधायक चंद्राकर ने कहा कि अन्नदाता किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, महतारी वंदन योजना में हर माह 1000 रुपये, पीएम आवास और कृषक उन्नति योजना का लाभ - यह सब मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रमाण है।

महापौर बाघमार एवं सभापति ने दुकानदारों को वितरित किए 300 जोड़ी डस्टबिन



श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और व्यापारियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से महापौर अलका बाघमार एवं सभापति श्याम शर्मा ने आज इंदिरा मार्केट क्षेत्र में दुकानदारों को 300 जोड़ी डस्टबिन वितरित किए। इस दौरान महापौर एवं जनप्रतिनिधियों ने फूल लाइन से प्रिया श्रृंगार सदन, सदर बाजार, मान होटल लाइन से होते हुए हटरी बाजार तक दुकानों में पहुंचकर व्यापारियों को डस्टबिन प्रदान किए और दुकान से निकलने वाले कचरे का उचित प्रबंधन करने की समझाइश दी।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग प्रभारी नीलेश अग्रवाल, एमआईसी सदस्य ज्ञानेश्वर ताम्रकर, मनीष साहू, शशि साहू, रंजीता पाटिल, मनीष कोठारी, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, कुणाल सहित निगम का अमला मौजूद रहा।

महापौर अलका बाघमार ने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान से निकलने वाले कचरे को निर्धारित डस्टबिन में ही एकत्रित करें तथा निगम के कचरा संग्रहण वाहन को ही सौंपें। सड़क, नाली एवं सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने से गंदगी फैलती है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी होती है। शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखना केवल निगम की नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। निगम प्रशासन स्वच्छता के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, ऐसे में व्यापारियों एवं नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी है। डस्टबिन वितरण के दौरान कुछ दुकानों के बाहर नालियों में कचरा पड़ा देखकर महापौर ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को नाली में कचरा फेंकने वाले दुकानदारों के विरुद्ध निगम के नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही दुकानदारों को स्पष्ट हिदायत दी कि दुकान के बाहर सड़क तक सामान फैलाकर व्यवसाय न करें।

निगम आयुक्त ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक

श्रीकंचनपथ न्यूज



भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुरूचि सिंह ने आज निगम सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों में लंबित कार्यों एवं प्रगतिरत कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों एवं मांगों का निराकरण, आगामी निकाय चुनाव के लिए पोलिंग बूथों में आवश्यक व्यवस्था, शहर की प्रकाश व्यवस्था, ई-ऑफिस प्रणाली में लंबित प्रकरणों तथा विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी गई। आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित कार्यों को गंभीरता से लेते हुए उनमें तेजी लाएं और निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करें।

बैठक में आयुक्त ने छत्तीसगढ़ शासन की सीएम हेल्पलाइन में नागरिकों द्वारा दर्ज कराई जा रही शिकायतों एवं मांगों की समीक्षा करते हुए उनका जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए जोन स्तर एवं वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए, ताकि प्राप्त शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेकर संबंधित विभाग के माध्यम से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए आयुक्त ने शहर के सभी पोलिंग बूथों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र में बिजली, पेयजल, बैठने की व्यवस्था एवं साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं को समय रहते दुरुस्त कर लें।

हिर्री खदान चिकित्सालय में ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का क्रियान्वयन

डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में बढ़ाया एक और कदम

श्रीकंचनपथ न्यूज



भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ विभाग के अंतर्गत संचालित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, भिलाई से संबद्ध हिर्री खदान अस्पताल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण करते हुए ई-सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। यह पहल सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

इस प्रणाली का क्रियान्वयन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफएडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का क्रियान्वयन उन्नत संगणना विकास केंद्र (सी-डैक) द्वारा किया जा रहा है। इसके तकनीकी सहयोग एवं क्रियान्वयन का समन्वय भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत सी-डैक की परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की टीम द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र के सहयोग से किया जा रहा है।

यह पहल मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं प्रमुख चिकित्सा सेवाएं डॉ. संबिता पंडा के मार्गदर्शन में क्रियान्वित की जा रही है। अस्पताल सेवाओं में डिजिटल तकनीक के समावेश के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं मरीजों के लिए सुविधाजनक बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महाप्रबंधक प्रभारी संजय कुमार परियोजना के क्रियान्वयन एवं समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एम एंड एचएस) डॉ. गुरमीत सिंह एवं डॉ. अमित अग्रवाल ने सी-डैक के समन्वय एचएमआईएस के विभिन्न मॉड्यूल के विकास में योगदान दिया है।

ई-सुश्रुत प्रणाली के अंतर्गत चिकित्सालय की प्रमुख सेवाओं का डिजिटल रूपांतरण किया जा रहा है। इसके तहत बाह्य रोगी विभाग के चिकित्सक कक्ष, औषधालय, सेवा क्षेत्र एवं इंजेक्शन कक्ष को इस व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। इससे चिकित्सालय के कार्यों को व्यवस्थित करने, विभागों के बीच तालमेल बढ़ाने तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इस व्यवस्था के तहत ई-सुश्रुत प्रणाली का एकीकरण भिलाई इस्पात संयंत्र के स्वास्थ्य साथी मोबाइल अनुप्रयोग के साथ किया गया है।

रावघाट खदान में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन

जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत, संस्कृति एवं योगदान को किया गया स्मरण

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के रावघाट खदान द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम खोडगांव, जिला नारायणपुर में जनजातीय गौरव दिवस जनपद अध्यक्ष पिंकी उसेंडी के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि मंगाउ राम कवाड़े एवं ग्राम खोडगांव की सरपंच सुश्री चैते नुरेटी विशेष रूप से उपस्थित थीं।



कार्यक्रम में क्षेत्र के लगभग आठ गांवों के सरपंचों तथा 23 गांवों के गायता, पटेल एवं पुजारियों सहित जनजातीय समाज के गणमान्य नागरिकों, ग्रामीणों, स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ बिरसा मुंडा के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। स्वागत उद्बोधन में भिलाई इस्पात संयंत्र के उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) एवं रावघाट खदान के प्रतिनिधि डॉ. यशवंत कुमार साहू ने आयोजन की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत और बिरसा मुंडा के आदर्शों का स्मरण करते हुए जनजातीय गौरव दिवस जैसे आयोजनों के महत्व को रेखांकित किया।

मुख्य अतिथि पिंकी उसेंडी ने अपने संबोधन में जनजातीय गौरव दिवस जैसे आयोजनों को निरंतर आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जनजातीय समाज एवं क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। मुख्य वक्ता मंगाउ राम कवाड़े ने अपने संबोधन में बिरसा मुंडा के प्रेरणादायी जीवन, उनके सामाजिक योगदान तथा स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने जनजातीय समाज के ऐतिहासिक संघर्ष एवं वर्तमान चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए समाज के लोगों से एकजुट रहने, अपने स्वाभिमान को बनाए रखने तथा अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया।

इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक उपेंद्र सिंह ने जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं एवं गौरवशाली विरासत का उल्लेख करते हुए बिरसा मुंडा के प्रेरणादायी व्यक्तित्व, संघर्ष एवं ऐतिहासिक योगदान का स्मरण किया। कार्यक्रम में स्थानीय वक्ता लखन नुरेठी एवं अविनाश बारसा ने गोंडी भाषा में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बिरसा मुंडा के सामाजिक एवं ऐतिहासिक योगदान को स्मरण करते हुए जनजातीय समाज की एकजुटता एवं सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने रावघाट खदान द्वारा क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकासात्मक एवं सामाजिक गतिविधियों की भी सराहना की। कार्यक्रम में उपस्थित जनजातीय समाज के गणमान्य नागरिकों को शॉल एवं श्रीफ्ल भेंटकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही रावघाट खदान में कार्यरत जनजातीय समाज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी विशेष रूप से सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम का संचालन रावघाट खदान के अतिरिक्त श्रम कल्याण अधिकारी दौलत राम पोयाम ने तथा धन्यवाद ज्ञापन उप महाप्रबंधक सचिन रंगारी ने प्रस्तुत किया।

Since 1972
CROWN®-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास खबर



सुशासन में हो रहा जनजाति समाज का सर्वांगीण उत्थान

बालोद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संवेदनशील नेतृत्व में चल रही 'सुशासन सरकार' से छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के उत्थान, सम्मान और समग्र विकास की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े ग्रामीण व आदिवासी परिवारों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंच रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में व्यापक सकारात्मक बदलाव आया है। इसका जीवंत उदाहरण जिले के आदिवासी बाहुल्य ग्राम देवारभाट की निवासी श्रीमती मोहनी बाई हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और महतारी वंदन योजना जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होकर अपने जीवन को नई दिशा दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय समाज के गौरव और सम्मान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज सुदूर अंचलों और आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। गांवों में पक्की सड़कों से लेकर हर घर तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचने से ग्रामीण परिवारों का जीवन सुगम हुआ है।

ग्राम देवारभाट की श्रीमती मोहनी बाई बताती हैं कि शासन की योजनाओं से उन्हें और उनके परिवार को लाभ मिल रहा है, जिससे वे अत्यंत खुश हैं। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिला है। जल जीवन मिशन के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सुविधा तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन भी प्राप्त हुआ है। 'महतारी वंदन योजना' के अंतर्गत हर माह आर्थिक सहायता मिल रही है।

जनजातीय शौर्य, त्याग, बलिदान और समृद्ध संस्कृति का साक्षी बनेगा धमतरी का ग्राम दुगली

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। जनजातीय समाज के अदम्य साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से धमतरी जिले के नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम दुगली में 17 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस का गरिमामय आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होने वाले इस समारोह में प्रदेश के राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन में जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में उसके अविस्मरणीय योगदान और विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।

जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही जनजातीय समाज के प्रमुखों का सम्मान कर



सामाजिक एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और समाज के उत्थान में उनके योगदान को रेखांकित किया जाएगा। यह अवसर नई पीढ़ी को जनजातीय महापुरुषों के संघर्ष, स्वाभिमान और राष्ट्रप्रेम की प्रेरणादायी गाथाओं से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।

समारोह में जनजातीय लोककला, पारंपरिक लोकनृत्य और विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से जनजातीय समाज की विशिष्ट जीवनशैली, लोकपरंपराओं, सांस्कृतिक विविधता और प्रकृति के साथ उसके गहरे जुड़ाव की झलक देखने को मिलेगी। आयोजन जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ नई पीढ़ी को अपनी गौरवशाली विरासत से जोड़ने का अवसर भी प्रदान करेगा।

कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा प्रदर्शनी एवं जानकारीपरक स्टॉल लगाए जाएंगे।

जनजातीय बच्चों के बंद पड़े 421 स्कूल फिर खुले

जनजातीय गौरव दिवस विशेष : 16 लाख से अधिक आदिवासी विद्यार्थी पा रहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के समग्र उत्थान और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को गढ़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक योजनाएं धरातल पर सार्थक परिणाम दे रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनजातीय बहुल और सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच को सुदृढ़ करने, शाला त्यागी दर (ड्रॉपआउट रेट) को न्यूनतम स्तर पर लाने और विद्यार्थियों को आधुनिक डिजिटल शैक्षणिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

वर्तमान में राज्य के कक्षा पहली से 12वीं तक के विद्यालयों में कुल 51 लाख 56 हजार 691 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इनमें से 16 लाख 12 हजार 748 विद्यार्थी (31.27 प्रतिशत) जनजातीय वर्ग से आते हैं। केवल शासकीय विद्यालयों की बात करें तो वहाँ अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों की संख्या 13 लाख 28 हजार 816 है, जो राज्य में जनजातीय शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान और विश्वास को दर्शाती है।

राज्य के बस्तर संभाग और अति-संवेदनशील जिलों जैसे सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा में शिक्षा का ढांचा मजबूत करने में नियद नेल्लनार योजना वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत पूर्व में बंद पड़े 458 विद्यालयों में से 421 बंद स्कूलों को 30 अक्टूबर 2026 तक पुन: सफलतापूर्वक



प्रारंभ कर लिया गया है। इससे नक्सल प्रभावित और दूरस्थ अंचलों के बच्चों को दोबारा मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिला है।

राज्य सरकार जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में आर्थिक एवं सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है।

स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 7.80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिछात्रवृत्ति योजना से लाभानिवत किया गया है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 54 हजार 225 छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए सरस्वती साइकिल योजना से लाभान्वित की गई है। नि:शुल्क गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को गणवेश तथा 14 लाख विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक का विरित कर लाभ पहुंचाया गया। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जैसे जिलों में 60 पोटा केबिन आवासीय विद्यालय तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 121 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं।

पीएम जनमन अभियान के तहत 40 नए छात्रावास (25 छात्रावास 50-सीटर और 15 छात्रावास 100-सीटर) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 42 नए छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है।

भाषा संबंधी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी और कुड़ुख जैसी स्थानीय बोली-भाषाओं में शिक्षण सामग्री विकसित की गई है।

इसके माध्यम से 13 हजार 35 शासकीय प्राथमिक स्कूलों के लगभग 3.60 लाख बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5 हजार 857 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और 1 हजार 388 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित किए गए हैं। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 1 लाख 55 हजार 341 विद्यार्थी आधुनिक शैक्षणिक परिवेश का लाभ उठा रहे हैं। वंचित वर्ग के बच्चों के लिए ओपन स्कूल परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा भी दी गई है।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ये ऐतिहासिक प्रयास छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के सशक्तिकरण, समान अवसर और एक समृद्ध व विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ ने आदिवासी महिलाओं के स्वाभिमान, अस्मिता और सशक्तिकरण का लिखा नया अध्याय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। भारत की स्वतंत्रता, संस्कृति और विरासत के संरक्षण में जनजातीय समाज का योगदान अविस्मरणीय है। अन्याय और शोषण के विरुद्ध 'उलगुलान' का शंखनाद करने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर मनाया जा रहा जनजातीय गौरव दिवस हमें अपने महान नायकों के साहस, स्वाभिमान और बलिदान का स्मरण कराता है। राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुण्डाधूर, शहीद गेंद सिंह, रानी दुर्गावती और ठाकुर रामप्रसाद पोटाई जैसे जननायकों का संघर्ष हमारी साझा विरासत है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जनजातीय समाज के गौरव और योगदान को राष्ट्रीय पहचान मिली है। वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किए जाने के बाद से जनजातीय अंचलों के विकास को नई गति मिली है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के संवेदनशील नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का संकल्प दूरस्थ वनांचलों तक पहुंच रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है।



जनजातीय समाज की मजबूती में माताओं और बहनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से हम उनके सम्मान, सुरक्षा, पोषण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। महतारी वंदन योजना से प्रदेश की 20 लाख 28 हजार 803 आदिवासी महिलाएं सीधे लाभान्वित हो रही हैं। यह आर्थिक सहायता उन्हें परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों में अपने स्तर पर निर्णय लेने का संबल देती है। जनजातीय महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मविश्वास को मजबूत करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

गरीब और वंचित परिवारों की बेटियों के विवाह का आर्थिक भार कम करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 2 हजार 72 विवाह संपन्न कराए गए हैं। इनमें लगभग 580 हितग्राही अनुसूचित जनजाति वर्ग की बेटियां हैं। यह पहल परिवारों को सहयोग देने के साथ बेटियों के सम्मान और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

माताओं और बच्चों के पोषण तथा प्रारंभिक देखभाल पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएम-जनमन अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बसाहटों में 191 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और सभी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इनके माध्यम से वनांचलों में बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा तथा गर्भवती माताओं को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान' (पीएम-जनमन) से छत्तीसगढ़ की पांच विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों-बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर के गांवों और बसाहटों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 1 हजार 545 ग्रामों और 2 हजार 365 बसाहटों का संतृप्तिमूलक विकास किया जा रहा है।

अब तक 24 हजार 218 पक्के आवास पूरे हो चुके हैं और 1 हजार 833 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं। 7 हजार 349 परिवारों का ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण किया गया है। इसके साथ ही 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 16 वनधन विकास केंद्र संचालित हैं।

विद्यार्थियों और शोधार्थियों को ओएनओएस के मार्फत मिली 13 हजार शोध पत्रिकाओं तक पहुँच

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में देश के पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर एक दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कृषि महाविद्यालय, रायपुर के सभागार में किया गया।

कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल थे। कार्यक्रम का उद्देश्य वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल के उद्देश्यों, प्रमुख विशेषताओं, उपलब्धता तथा इसके प्रभावी उपयोग के संबंध में प्रतिभागियों को जागरूक करना था। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इस पहल के माध्यम से केंद्रीकृत सदस्यता व्यवस्था के अंतर्गत देशभर के पात्र उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों को शोध प्रकाशनों एवं अकादमिक



पत्रिकाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना प्रारंभ की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को इसे स्वीकृति प्रदान की तथा इसका क्रियान्वयन 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ। योजना के प्रथम चरण (2025-2027) के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत देश के पात्र उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों को 30 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं तक एकीकृत डिजिटल पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, यू.जी.सी. द्वारा किया जा रहा है।

शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जैसे कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों को कृषि विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, फसल सुधार, पादप संरक्षण, जलवायु परिवर्तन एवं टिकाऊ कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम अंतरराष्ट्रीय शोध एवं वैज्ञानिक जानकारी तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. शोधार्थियों के शोध कार्य की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग एवं बहुविषयक अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में ओएनओएस योजना के प्रभारी डॉ. एसके त्रिपाठी ने कहा कि ओएनओएस योजना कृषि अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक ज्ञान और नवीनतम वैज्ञानिक शोध तक पहुंच उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है। इसका प्रभावी उपयोग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता, नवाचार, अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सहयोग तथा कृषि तकनीकी विकास को नई दिशा प्रदान कर सकता है।

शहीदों का बलिदान राष्ट्र की अमूल्य धरोहर : राज्यपाल डेका

श्रीकंचनपथ समाचार

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका आज शाम रायगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक ऑडिटोरियम में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित शौर्य दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों का सम्मान किया और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दिए गए उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया।

समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि देश की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए वीर जवानों का त्याग और समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। एक सैनिक का बलिदान केवल उसका व्यक्तिगत बलिदान नहीं होता, बल्कि उसका पूरा परिवार भी राष्ट्र के लिए त्याग करता है। शहीदों के परिवारों का सम्मान करना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों के प्रति सम्मान और सहयोग किसी एक आयोजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके सुख-दुख में सहभागी बनना हम सभी



का दायित्व है।

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध सुरक्षा बलों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। अनेक जवानों ने देश और प्रदेश की शांति एवं सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने युवाओं से शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके साहस, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति केवल नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना और राष्ट्र के विकास में योगदान देना भी सच्ची देशभक्ति है। राज्यपाल श्री डेका ने सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। साथ ही शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मेमोरियल ट्रस्ट को इस प्रेरणादायी आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने सभी से शहीदों के त्याग और बलिदान को सदैव स्मरण रखने तथा सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित एवं विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लेने की अपील की।

इस अवसर पर सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह, ब्रिगेडियर आर शंकर, कमाण्डेड अजय सिंह बिसेन, सुभाष त्रिपाठी, श्रीमती आशा त्रिपाठी, राहुल शुक्ला, राजेश पटनायक सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

राज्यपाल रमेन डेका ने भारतीय सेना में जाने के इच्छुक विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। जिसमें सैनिक स्कूल में अध्ययनरत अंकित पटेल, तोयम पटेल, स्तव्य साहू, जयेश सिदार एवं सृष्टि राठिया तथा कक्षा 9वीं के नवनीत मेहर, भुवनेश पटेल एवं अर्नव गुप्ता शामिल थे। इसी प्रकार ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की कलाडी श्रीनिधि एवं भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के आर.बालाजी को प्रोत्साहन राशि दी गई।





फैशन इवेंट में रेड ड्रेस पहन शरवरी ने बिखेरा जलवा



मशहूर फैशन डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला अपने शानदार और भव्य डिजाइन्स के लिए जाने जाते हैं। भारतीय फैशन की दुनिया में इस डिजाइनर जोड़ी ने पारंपरिक कारीगरी और हैंड एम्ब्रॉयडरी को नए अंदाज में पेश कर खास पहचान बनाई। अब इस जोड़ी ने आर्ट मुंबई में अपने नए फैशन शो 'डिस्को इनफर्नो' से एक बार फिर सबका ध्यान खींच लिया।

'डिस्को इनफर्नो' के जरिए अबू जानी और संदीप खोसला ने 70 और 80 के दशक के डिस्को दौर को अपने खास भव्य अंदाज में दोबारा जीवंत किया। इस शो में सिर्फ वेस्टर्न डिस्को ही नहीं, बल्कि भारतीय संगीत के उस दौर की झलक भी देखने को मिली, जब सिंथेसाइजर की धुनों पर पूरी पीढ़ी थिरकती थी। चमक-दमक, रंगों और स्टाइल से भरपूर इस शाम में फैशन और संगीत का शानदार मेल देखने को मिला।

शरवरी ने बिखेरा जलवा

इस शाम की खास आकर्षण अभिनेत्री शरवरी रहीं, जिन्होंने डिजाइनर जोड़ी के लिए रैंप वॉक किया। वह इस शो की म्यूज बनीं और अपने शानदार लुक से सबका ध्यान खींच लिया। शरवरी ने 'राज' कलेक्शन से प्रेरित मल्टीकलर स्वारोवस्की क्रिस्टल और स्टोन्स से सजी ड्रेस पहनी थी। इसके साथ उन्होंने कॉन्सेप्ट ड्रेप रेड ड्रेस भी पहनी, जिसे क्रिस्टल और स्टोन से सजे ब्लाउज के साथ स्टाइल किया गया था। उनके लुक को चमकदार स्टोन चेन की कई लेयर्स ने और खास बना दिया।

क्या बोलीं शरवरी?

शरवरी ने शो का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'अबू सर और संदीप सर जिस तरह भारतीय विरासत की खूबसूरती को आधुनिक सोच के साथ जोड़ते हैं, वह बेहद खास है। इस साल की थीम 'डिस्को इनफर्नो' उनके क्रिएटिव विजन को एक नया आयाम देती है।

मैंने पहले भी उनके डिजाइन पहने हैं और हमेशा इस बात की सराहना की है कि वे भारतीय कारीगरी को कितनी खूबसूरती से नए अंदाज में पेश करते हैं। उनके लिए आर्ट मुंबई में रैंप वॉक करना मेरे लिए खास अनुभव है, क्योंकि यह सिर्फ खूबसूरत कपड़े पहनने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी उस डिजाइन फिलॉसफी का जश्न है, जो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए लगातार नए प्रयोग करती है।'

जया बच्चन के अंदाज ने खींचा ध्यान

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें जया बच्चन इस इवेंट में डिजाइनर के साथ अंदर जाते हुए नजर आईं। इस दौरान पैपराजी ने उन्हें फोटो क्लिक करवाने के लिए भी बोला, लेकिन अभिनेत्री बिना रुके मुस्कुरा कर चली गईं। बता दें कि जया बच्चन इस इवेंट में अपने दोस्तों और डिजाइनर जोड़ी अबू जानी-संदीप खोसला का हौसला बढ़ाने पहुंची थीं।

'टॉक्सिक' में इंटीमेट सीन देकर घिरी थीं कियारा, बताया कैसा था सिद्धार्थ का रिएक्शन

बॉलीवुड में शादी के बाद अभिनेत्रियों के ऑनस्क्रीन किरदारों और उनके फैसलों को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं। खासकर जब कोई अभिनेत्री शादी और मां बनने के बाद पर्दे पर बोल्ड या इंटीमेट सीन करती है, तो उसे सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है।



ऐसा ही कुछ कियारा आडवाणी के साथ भी हुआ, जब फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के साथ उनके इंटीमेट सीन को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। अब अभिनेत्री ने इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि इस मामले पर पति सिद्धार्थ मल्होत्रा का क्या रिएक्शन था।

कियारा ने बताया कि शादी और मां बनने के बाद फिल्म में उनके ऑनस्क्रीन चुनावों को लेकर इंटरनेट पर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। कियारा ने साफ किया कि सोशल मीडिया पर हो रही बातों से सिद्धार्थ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इस मुद्दे को कभी परेशानी नहीं माना और न ही इस बारे में उनसे कोई सवाल किया। अभिनेत्री ने कहा, 'उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की। हमने इस पर कभी चर्चा भी नहीं की। इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा और वह बिल्कुल भी परेशान नहीं थे।'

सोशल मीडिया पर हुई आलोचना को लेकर कियारा ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को इस तरह की बातों का सामना दशकों से करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'यह कई वर्षों से, दशकों से होता आ रहा है। ऐश्वर्या से लेकर कई शानदार अभिनेत्रियों को इसका सामना करना पड़ा है।'

हालांकि, अपने किरदार के लिए मिली तारीफों से उन्हें हिम्मत मिली। कियारा ने कहा कि इस फिल्म में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना उनके करियर के लिए अहम रहा। उन्होंने इस भूमिका को अपने करियर का एक परिभाषित करने वाला किरदार बताया।

प्यार का प्रेशर कुकर शो होस्ट करेंगी शिल्पा शेट्टी



बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी रिलेशनशिप रियलिटी शो 'प्यार का प्रेशर कुकर' को होस्ट करने जा रही हैं। शो के मेकर्स के अनुसार, यह शो ऐसे कपल्स को एक साथ लाएगा जो अपने रिश्तों में किसी मोड़ पर आकर फंस गए हैं।

एक ही घर में रहने के दौरान, प्रतिभागियों को उन सवालों के जवाब देने होंगे जिनसे वे अब तक बचते आ रहे हैं। इस प्रक्रिया में उनके माता-पिता भी शामिल होंगे, जो उन्हें एक जरूरी 'रियलिटी चेक' देंगे, ताकि स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके और सच सामने आ सके।

शो के बारे में बात करते हुए शिल्पा ने कहा, 'आजकल रिश्तों में कई नए शब्द जुड़ गए हैं, जैसे 'सिचुएशनशिप', 'ब्रेडक्रंबिंग' और 'बेंचिंग'। इस सब के बीच असल स्पष्टता कहीं खो गई है। चाहे रिश्ता नया हो या वर्षों से चला आ रहा कोई पुराना रिश्ता, एक ऐसा मोड़ जरूर आता है, जब किसी को सही और जरूरी सवाल पूछने ही पड़ते हैं। 'प्यार का प्रेशर कुकर' की जो बात मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करती है, वह है रियलिटी फॉर्मेट पर इसका एक नया नजरिया।'

अपनी बात कहने के लिए प्रेरित करता है शो

शिल्पा ने आगे कहा 'यह भारत का पहला ऐसा रिलेशनशिप शो है, जहां माता-पिता प्रतिभागियों को 'रियलिटी चेक' देते हैं। यह शो कपल्स के साथ-साथ उनके माता-पिता के लिए भी काफी दिलचस्प है, जो यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि असल में क्या चल रहा है। यह एक ऐसा शो है जो लोगों को वह बात कहने के लिए प्रेरित करता है जो वे वास्तव में कहना चाहते हैं। मैं इसे होस्ट करने के लिए बहुत उत्साहित हूं।'

शिल्पा शेट्टी का वर्कफ्रंट

आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी फिटनेस को लेकर काफी जागरूक हैं।
उन्होंने फिटनेस पर दो किताबें लिखी हैं।
फिल्म 'बाजीगर' (1993) से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा।
आखिरी बार उन्हें पैन इंडिया फिल्म 'केडी: द डेविल' में नजर आईं। इसमें संजय दत्त भी थे।

'रामायण पार्ट 2' की 60% शूटिंग पूरी

हनुमान और वानर सेना पर रहेगा खास फोकस

रणबीर कपूर की 'रामायण पार्ट 2' की 60 फीसदी शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म के दूसरे भाग में हनुमान और वानर सेना का भव्य रूप देखने को मिलेगा। फिल्म दिवाली 2028 में रिलीज होगी।

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' के दूसरे पार्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म के सिनेमैटोग्राफर पंकज कुमार ने खुलासा किया है कि सीक्वल की करीब 60 फीसदी शूटिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि दूसरा पार्ट पहले से ज्यादा भव्य होने वाला है। इसमें हनुमान और पूरी वानर सेना जैसे कई CGI किरदार नजर आएंगे, जिन पर काफी काम किया जाना बाकी है।



दिवाली 2028 में रिलीज होगा दूसरा पार्ट

'रामायण' का पहला पार्ट हनुमान की छोटी सी झलक के साथ खत्म होता है। फिल्म में सनी देओल भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन मेकर्स ने उनका पूरा लुक अभी सामने नहीं लाया है। इसे दूसरे पार्ट के लिए रहस्य बनाकर रखा गया है। पहले 'रामायण पार्ट 2' को दिवाली 2027 में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसकी रिलीज डेट बदलकर दिवाली 2028 कर दी गई। पहले पार्ट के एंड क्रेडिट्स में भी मेकर्स ने इसकी पुष्टि की थी।

किष्किंधा से लंका तक आगे बढ़ेगी कहानी

दूसरे पार्ट में भगवान राम और लक्ष्मण की यात्रा किष्किंधा तक पहुंचेगी, जहां उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होगी। कहानी में बाली वध और सुग्रीव की मदद से सीता की तलाश में लंका तक पहुंचने का सफर भी दिखाया जाएगा। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में अरुण गोविल राजा दशरथ, लारा दत्ता कैकेयी, इंदिरा कृष्णन कौशल्या और काजल अग्रवाल मंदोदरी की भूमिका निभा रही हैं।





'रामायण पार्ट 2' में दिखेगा बड़ा विजुअल स्केल

पंकज कुमार ने बताया कि दूसरे पार्ट की लगभग 60 फीसदी शूटिंग पूरी हो चुकी है। हालांकि, फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और मोशन कैप्चर का काफी काम अभी बाकी है। उनके मुताबिक, दूसरा पार्ट पहले से ज्यादा ग्रैंड होगा और इसमें किरदारों की संख्या भी अधिक रहेगी। पंकज ने खास तौर पर हनुमान और पूरी वानर सेना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन किरदारों को पर्दे पर उतारने के लिए काफी बारीकियों पर काम करना होगा।

त्योहारों के दौरान पेट फूलने की समस्या से राहत पाने के लिए अपनाएं ये पांच तरीके



हल्का और कम मसालेदार खाना खाएं

त्योहारों के दौरान तली चीजें, बिरयानी, पनीर, मिठाई और अन्य कई व्यंजनों का सेवन किया जाता है, जो पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं। इसलिए इनका सेवन कम करें और हल्का भोजन करें।

इसके लिए आप दाल, चावल, रोटी और सब्जी का सेवन कर सकते हैं। इस तरह के भोजन से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और पेट फूलने की समस्या से राहत मिलती है।

पानी का करें भरपूर सेवन

पानी का सेवन पेट फूलने की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। यह पाचन को ठीक करने और पेट की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है।

इसके अतिरिक्त यह शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। इसलिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं।

इसके साथ ही आप इसमें नींबू का रस या पुदीना भी मिला सकते हैं। यह आपके पाचन को बेहतर बनाएगा।

फाइबर युक्त भोजन खाएं

फाइबर युक्त भोजन का सेवन पेट फूलने की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है। फाइबर पाचन तंत्र को ठीक रखने के साथ-साथ आंत की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है।

इसके लिए आप अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, दलिया, ओट्स, चिया बीज आदि को शामिल कर सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों से पेट की समस्याओं से बचने में सहायता मिलती है।

गर्म पानी से नहाएं

गर्म पानी से नहाने से भी पेट फूलने की समस्या दूर हो सकती है। दरअसल, गर्म पानी से नहाने से रक्त का बहाव बेहतर होता है, जिससे पाचन तंत्र भी ठीक से काम करता है।

इसके अलावा इससे पेट की सूजन कम होती है और आराम महसूस होता है। साथ ही इससे शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।

हल्की एक्सरसाइज करें

पेट फूलने की समस्या से राहत पाने के लिए हल्की एक्सरसाइज करना भी फायदेमंद हो सकता है। इससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और आंत की सूजन कम होती है। आप रोजाना सुबह या शाम टहल सकते हैं।

त्योहारों का मौसम आते ही हर कोई तरह-तरह के व्यंजनों का आनंद लेने लगता है, लेकिन इसके कारण पेट फूलने की समस्या हो सकती है। हालांकि, इसे सामान्य माना जाता है, लेकिन इससे असुविधा महसूस हो सकती है। अगर आप भी त्योहारों के दौरान इस समस्या से परेशान रहते हैं तो आइए आज हम आपको इसके लिए 5 असरदार तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप पेट फूलने की समस्या से राहत पा सकते हैं।

इसके अलावा आप योगाभ्यास भी कर सकते हैं। इसके लिए आप वज्रासन, बालासन, शवासन, पवनमुक्तासन आदि को अपना सकते हैं। इनसे पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है।

खास-खबर

मंजूरी प्राप्त निविदा वाले कार्यों के कार्यादेश जल्द जारी करने के निर्देश

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज तीन अलग-अलग बैठकें लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में बस्तर संभाग में आर.आर.पी. और आर.सी.पी. एल.डब्ल्यू. ई.ए. के तहत निर्माणाधीन सड़कों व पुलों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण तथा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों से बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित करते हुए सभी कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कार्यों में प्रगति नहीं लाने वाले और हीला-हवाला करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करते हुए उनके पंजीयन निरस्त करने के निर्देश दिए। बंसल ने सड़कों पर ब्लैक-स्पॉट्स को दूर करने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने आर.टी.ओ. और एस.पी. कार्यालयों से समन्वय कर ब्लैक-स्पॉट्स दूर करने आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने इसके लिए तत्परता से काम कर सड़कों पर जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चत करने के निर्देश दिए।

जिले में स्थापित होगी 10 टन क्षमता की ऑयल एक्सट्रेशन यूनिट

सूरजपुर। कृषि अधिकारी ने जानकारी दी है कि केन्द्रीय योजना नेशनल मिशन ऑन लाईन एडिबल ऑयल-ऑयल सीड योजनान्तर्गत जिला सूरजपुर मे 01 नग तेल निकालने की मशीन (ऑयल एक्सट्रेशन यूनिट) 10 टन क्षमता स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, योजनान्तर्गत ऑयल एक्सट्रेक्शन यूनिट में लागत पर अनुदान राशि 33 प्रतिशत (अधिकतम राशि 9.90 लाख रुपये) हैं इच्छुक कृषक उत्पादक समूह , बीज उत्पादक सहकारी समिति, सहकारी एवं प्राइवेट इंडस्ट्रीज 20 नवंबर 2026 अपरान्ह 05:00 बजे तक आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज स्पीड पोस्ट/रजिस्टर डाक के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति सह अभिलेख सहित कार्यालय उप संचालक कृषि जिला सूरजपुर (छ.ग.) भेज सकते है, आवेदन की विस्तृत जानकारी कलेक्टर कार्यालय एवं कार्यालय उप संचालक कृषि के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।

बेटियों को आत्मनिर्भर और आत्मरक्षा में सक्षम बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ योग आयोग की पहल, अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने किया छात्राओं का उत्साहवर्धन

आदर्श पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास में छात्राओं को सिखाए गए आत्मरक्षा के गुर, अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी चंचल डिक्सेना ने दिए प्रशिक्षण के टिप्स

श्रीकंचनपथ समाचार

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के बस्तर प्रवास के दौरान कोंडागांव स्थित आदर्श पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्राओं को आत्मरक्षा की व्यावहारिक तकनीकों से अवगत कराया गया और विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की सुरक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया।





कार्यक्रम का विशेष आकर्षण अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी एवं मार्शल आर्ट चैंपियन व ट्रेनर चंचल डिक्सेना रहीं। उन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण तरीके सिखाए और बताया कि किसी भी अप्रिय या आपातकालीन परिस्थिति में घबराने के बजाय सतर्कता, आत्मविश्वास और सूझबूझ के साथ स्वयं की रक्षा कैसे की जा सकती है।

प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं को छेड़छाड़ अथवा गलत मंशा से की जाने वाली गतिविधियों का सामना करने के लिए कई व्यावहारिक तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। उन्हें बताया गया कि अपने पास सामान्य रूप से उपलब्ध रहने वाली वस्तुओं, जैसे पेन, हेयर क्लिप, स्कार्फ आदि का आवश्यकता पड़ने पर आत्मरक्षा के लिए किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। साथ ही स्वयं के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा में भी किस तरह मददगार बना जा सकता है, इसकी जानकारी दी गई।

चंचल ने छात्राओं के बीच उत्साह और आत्मविश्वास का संचार करते हुए कहा कि सशक्त बनने के लिए सबसे पहले अपने मन और मस्तिष्क को मजबूत बनाना जरूरी है। आत्मरक्षा केवल शारीरिक ताकत का विषय नहीं, बल्कि जागरूकता, आत्मविश्वास, मानसिक दृढ़ता और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी है। उन्होंने कहा कि योग ऐसी साधना है, जो शरीर के साथ मन, विचार और चिंतन को भी मजबूत बनाती है। योग के माध्यम से विकसित अनुशासन और मानसिक मजबूती आत्मरक्षा के गुणों को और प्रभावी बनाते हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की बेटियों को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल है।

प्रत्येक बेटी को यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में स्वयं की सुरक्षा के लिए सक्षम है। योग के साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण को जोड़कर प्रदेश की युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के दूरस्थ, आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। इस दिशा में आगामी समय में बड़ी कार्ययोजना तैयार कर प्रशिक्षण को और विस्तार देने की पहल की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को केवल आत्मरक्षा की तकनीक सिखाना ही नहीं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, साहस, जागरूकता और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना भी रहा।

योग और आत्मरक्षा के समन्वय से बेटियों को सुरक्षित, सशक्त और सक्षम बनाने की यह पहल प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में निज सचिव देवीलाल पटेल, प्रेग्नेंसी योग विशेषज्ञ डॉ. दुर्गा साहू, अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी एवं मार्शल आर्ट ट्रेनर चंचल डिक्सेना, सहायक अधीक्षक अरुण कुमार साहू तथा कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर एवं योग शिक्षिका पूजा साहू उपस्थित रहीं। इस दौरान छत्तीसगढ़ योग आयोग के मीडिया प्रभारी सीमांत कश्यप भी मौजूद रहे। योग से मानसिक मजबूती और आत्मरक्षा से सुरक्षा का आत्मविश्वास ङ्क इसी संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ योग आयोग बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

भखारा में नवीन उप पंजीयक कार्यालय का विधायक चंद्राकर ने किया शुभारंभ

कार्यालय शुरू होने से भखारा तहसील के 73 गांवों को मिलेगी पंजीयन सेवाओं की सुविधा, प्रदेश का 121वां और धमतरी जिले का चौथा उप पंजीयक कार्यालय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। धमतरी जिले की भखारा तहसील को पंजीयन सेवाओं के विस्तार की नई सौगात मिली है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में प्रदेश में पंजीयन सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने आज भखारा में नवीन उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ किया। विधायक श्री चंद्राकर ने कहा कि जिले में पंजीयन सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को पंजीयन संबंधी कार्यों में सुविधा मिलेगी।

यह प्रदेश का 121वां और धमतरी जिले का चौथा उप पंजीयक कार्यालय है। इसके शुरू होने से भखारा तहसील के 73 गांवों के नागरिकों को पंजीयन संबंधी सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। अब उन्हें इन कार्यों के लिए दूरस्थ कार्यालयों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी।



कैलाश साहू ने कराया पहला पंजीयन: शुभारंभ अवसर पर रायपुर निवासी कैलाश साहू ने पहला विक्रय विलेख पंजीयन कराया। इसके साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया भी तत्काल पूरी की गई। पंजीयन के बाद विधायक चंद्राकर ने उन्हें बी-1 और खसरा की प्रति प्रदान की। श्री साहू ने पंजीयन प्रक्रिया में मिली सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि भखारा में कार्यालय शुरू होने से लोगों को पंजीयन के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा।

जिला पंजीयक आशु अग्रवाल ने कहा कि नए उप पंजीयक कार्यालय से क्षेत्रवासियों को घर के नजदीक पंजीयन संबंधी सेवाएं मिलेंगी। इससे जिला मुख्यालय या दूरस्थ कार्यालयों तक बार-बार जाने की जरूरत कम होगी और नागरिकों के समय एवं श्रम की बचत होगी।

इस अवसर पर भखारा-भठेली नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति हरख जैन, कलेक्टर अबिनाश मिश्रा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और नागरिक उपस्थित रहे।

धान खरीदी कार्य पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराएं - कुणाल दुदावत

श्रीकंचनपथ समाचार

कोरबा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2027 तक संचालित होगी। किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी।

खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों-कर्मचारियों एवं धान उपार्जन केंद्रों के समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर दुदावत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी शासन की प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान कोचियों, बिचौलियों एवं व्यापारियों से धान की खरीदी किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। यदि किसी उपार्जन केंद्र में इस प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरे जिलों से अवैध रूप से धान की आवक तथा अवैध खरीदी-बिक्री पर प्रभावी निगरानी रखी जाए।

सड़क कनेक्टिविटी की नई राह, कोरबावासियों का आवागमन होगा आसान

श्रीकंचनपथ समाचार

कोरबा। चांपा की ओर जाने वाले कोरबावासियों को लंबे समय से आवागमन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब उरगा से सीतामणी तक 9.40 किलोमीटर सड़क निर्माण को 34 करोड़ 33 लाख 4 हजार 635 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने से इस मार्ग पर बेहतर आवागमन की उम्मीद जगी है।

सड़क बनने से कोरबा की बिलासपुर-उरगा-हाटी भारतमाला मार्ग से कनेक्टिविटी मजबूत होगी और चांपा रेलवे स्टेशन सहित चांपा की ओर जाने वाले मार्गों तक पहुंचना अधिक सुविधाजनक होगा।

शहर के भीतर आवाजाही आसान बनाने के लिए गौमाता चौक से रेलवे स्टेशन तक लगभग 2.90 किलोमीटर सड़क निर्माण को भी 13 करोड़ 13 लाख 62 हजार 678 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस मार्ग से रेलवे स्टेशन और गौमाता चौक के बीच आवागमन सुगम होगा। सीतामढ़ी और इमलीडुग्गू रेलवे क्रॉसिंग की ओर जाने वाले लोगों को भी बेहतर मार्ग उपलब्ध होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को रोजमर्रा के आवागमन में राहत मिलेगी।

दोनों सड़क परियोजनाओं पर कुल 47 करोड़ 46 लाख 67 हजार 313 रुपये खर्च होंगे। इनके निर्माण से कोरबा की बाहरी कनेक्टिविटी और शहर के भीतर यातायात, दोनों को मजबूती मिलेगी। लंबे समय से बेहतर सड़क सुविधा की जरूरत महसूस कर रहे नागरिकों के लिए ये स्वीकृतियां सुगम और सुविधाजनक आवागमन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री जी.आर. जांगड़े ने बताया कि दोनों सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का पालन करते हुए कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन मार्गों के बनने से नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री अरुण साव, उद्योग एवं श्रम मंत्री एवं स्थानीय कोरबा विधायक लखन लाल देवांगन तथा कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन और समन्वय से इन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। एसईसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 392वीं बैठक में प्रशासनिक सहमति के बाद जिला प्रशासन और एसईसीएल के बीच 9 अक्टूबर 2026 को एमओयू निष्पादित किया गया। दोनों मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ उक्त मार्ग का निरीक्षण किया गया और कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये।

खेतों में कटाई की रफ्तार, केंद्रों में खरीदी की तैयारी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। कोरिया जिले में धान कटाई ने रफ्तार पकड़ ली है। किसान खेत-खलिहानों में फसल समेटने में जुटे हैं। वहीं, जिला प्रशासन खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है।

जिले की 21 आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के अंतर्गत संचालित 24 उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर से खरीदी प्रारंभ होगी। इस वर्ष जिले में 1 लाख 37 हजार 49 मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने सभी केंद्रों में खरीदी से पहले आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नोडल अधिकारियों को केंद्रों का भौतिक सत्यापन पूर्ण करने के लिए कहा गया है। खरीदी प्रक्रिया एवं दायित्वों के संबंध में नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण 13 नवंबर को होगा। ऑनलाइन टोकन की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हो चुकी है।

जिला खाद्य कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस वर्ष धान विक्रय के लिए कुल 24,116 किसान पंजीकृत हैं। इनमें 992 नए किसान शामिल हैं। कुल पंजीकृत रकबा 28,834.67 हेक्टेयर है। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 थी। पिछले खरीफ विपणन वर्ष में 23,438 किसान पंजीकृत थे।

इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या में 678 की वृद्धि हुई है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर के कोरिया प्रक्षेत्र के नोडल कार्यालय के अनुसार, खरीफ वर्ष 2026 में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य 68 करोड़ रुपये निर्धारित है।

नागरिकों और विद्यार्थियों के आधार व बायोमेट्रिक अपडेट कार्य को दें सर्वोच्च प्राथमिकता-मुख्य सचिव

उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में आधार सेचुरेशन और पारदर्शी डिजिटल गवर्नेंस पर विशेष जोर, स्कूलों में चलाए जाएंगे विशेष अभियान

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से हर पात्र हितग्राही तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने आधार से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राज्य में आधार से संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र नागरिकों, विद्यार्थियों और आंगनबाड़ियों में दर्ज बच्चों के अभिभावकों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।



मुख्य सचिव ने स्कूली बच्चों के आधार पंजीयन और बायोमेट्रिक अद्यतन की समीक्षा करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग और संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिले, इसके लिए आधार का होना अनिवार्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार नामक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही, बच्चों की आयु के आधार पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का नए आधार नामांकन, 5 और 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट किया जाए।

स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में जन्मे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करने से पहले ही अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए। राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के शत-प्रतिशत आधार नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ आदिवासी बसाहटों और ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य सत्यापन पोर्टल पर 18 वर्ष से अधिक आयु के नए नामांकन और 100 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आधार डेटा के सत्यापन की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

जिला कलेक्टरों को मॉनिटरिंग के निर्देश: मुख्य सचिव विकासशील ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में लंबित आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट के मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सेवा केंद्रों की सुलभता बढ़ाई जाए ताकि किसी भी नागरिक को असुविधा न हो।

पारदर्शी डिजिटल गवर्नेंस और योजनाओं का एकीकरण: बैठक के अंत में आधार की उपयोगिता को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रभावी ढंग से जोड़ने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि योजनाओं में आधार प्रमाणीकरण के उपयोग से प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक शासकीय सहायता का त्वरित लाभ पहुँचेगा।

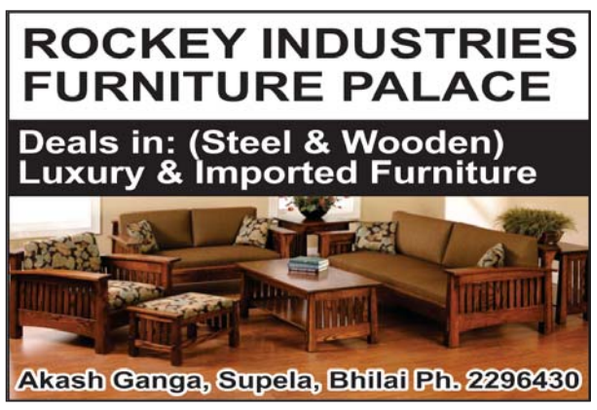
बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया सहित विभिन्न विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जिले के 73 केंद्रों में नोडल अधिकारी नियुक्त

कोरबा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए जिले के सभी 73 उपार्जन केंद्रों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। खरीदी 15 नवंबर से सहकारी समितियों के माध्यम से होगी। कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा जारी आदेश के अनुसार नोडल अधिकारी खरीदी शुरू होने से पहले केंद्रों की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे और खरीदी अवधि में व्यवस्था की निगरानी करेंगे। केंद्रों में बिजली, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र, बायोमेट्रिक डिवाइस, सीसीटीवी, बारदाने, हमाल, पेयजल और प्राथमिक उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। खरीदी शुरू होने के बाद केंद्र में उपलब्ध धान और बारदानों का नियमित भौतिक सत्यापन किया जाएगा।











खास खबर

ओडिशा-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बड़ी लापरवाही, नशे में धुत्त मिला गार्ड

रायगढ़। जिले के तमनार ब्लॉक अंतर्गत हमीरपुर स्थित ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर तैनात सरकारी गाड़ियों की लचर फायरिंग दिखी। 11 नवंबर की रात करीब आबकारी विभाग का प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड शराब के नशे में बेसुध सोता हुआ पाया गया। वहीं 12 नवंबर की सुबह 8 बजे तक मंडी विभाग के चेकपोस्ट पर भी कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने बताया कि आबकारी विभाग के गार्ड और उनके साथियों द्वारा चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली के आरोप भी लगाए हैं। विदित हो कि हमीरपुर स्थित ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा एक महत्वपूर्ण विवादित मार्ग है। इस मार्ग से रात के समय भारी ट्रैफिक, ट्रकों, पिकअप और चार पहियों की आवाजाही होती है। ऐसे संवेदनशील मार्ग पर गांजा, अवैध खनिज, स्पंज आयरन, सब्जियों के अवैध परिवहन सहित अन्य निषेध सामग्री की घटती रोकथाम के लिए निरंतर निगरानी और मुस्तैद जांच व्यवस्था बेहद जरूरी है। लेकिन यदि जांच के लिए तैनात कर्मचारी ही नशे में बेसुध नींद मिले तो सीमा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है।

डम्पर की चपेट में आने से भाई-बहन की मौके पर मौत

रायगढ़। जिले में भारी बर्फबारी का कहर लगातार जारी है। तमनार रोड पर एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भारी वाहन डंपर ने बुलेट सवार भाई-बहन को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार मरे की पहचान 21 वर्षीय घनश्याम डनसेना और उनकी 23 वर्षीय बहन कुंती डनसेना के रूप में हुई है। जो मिलूपारा के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि दोपहर लगभग 11.30 बजे दोनों भाई-बहन अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से रायगढ़ जाने के लिए निकले थे। इसी सफर के दौरान जब वे तमनार रोड स्थित जिंदल गेट नंबर 2 के पास पहुंचे, तभी एक बेकाबू डंपर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों को बचने या संभालने का कोई मौका नहीं मिला और उन्होंने गतिविधियों पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और सुरक्षात्मक के बाद दोनों शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया है। एक ही झटके में परिवार के दो जवान बच्चों की मौत की खबर से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस दर्दनाक घटना ने भारी बर्फबारी की बेलगाम रफ्तार पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बिलासपुर में जुआरियों पुलिस का पर एक्शन

बिलासपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के कोदू चौक मैदान में तीन अलग-अलग जुआ फड़ पर पुलिस ने दबिश दी। मौके से 11 जुआरियों को ताश पत्ती पर दांव लगाते गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है । पुलिस ने तीनों फड़ों से ताश की गड्डियां के साथ कुल 13,360 रुपये नकद जब्त किया है।

मारपीट और लूट मामले में नाबालिग समेत 2 गिरफ्तार

बिलासपुर। भाई दूज मनाकर लौट रहे बाइक सवार युवकों के साथ गनियारी में मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ कोटा पुलिस ने शिकंजा कसा है। तीन आरोपियों ने चक्राकुंड मोड़ के पास गाली-गलौज कर लात-घूंसों और बेल्ट से हमला किया था। इसके बाद दोनों युवकों के मोबाइल लूटकर मौके से फरार हो गए थे। मुख्य आरोपी कुनानू वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं वारदात में शामिल नाबालिग भी पुलिस हिरासत में है। दोनों के कब्जे से लूटे गए दो मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त किए हैं।

15 साल के किशोर को बालिग बताकर भेजा जेल

एक महीना पहले बाल न्यायालय ने लगाया था जुर्माना, पुलिस ने अब उसे बालिग मानकर किया गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। बिलासपुर के सरकंडा पुलिस की एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में उम्र को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने 15 साल के किशोर की उम्र रिकॉर्ड में 18 साल दर्ज कर उसे वयस्क आरोपियों के साथ न्यायालय में पेश किया और सेंट्रल जेल भेज दिया। जबकि, करीब एक महीने पहले बाल न्यायालय ने उसकी उम्र 15 साल मानते हुए 1500 रुपए जुर्माने पर उसे रिहा किया था।





परिजनों ने इसके समर्थन में बाल न्यायालय की सील लगी रसीद भी दिखाई है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि किशोर ने पूछताछ में अपनी जन्मतिथि 8 नवंबर 2008 बताई थी। उस समय परिजनों की ओर से उम्र से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। अब परिजनों द्वारा दस्तावेज दिए जाने पर उनकी जांच कराई जाएगी।

दरअसल, सरकंडा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान विवाद और हंगामा करने के आरोप में छह लड़कों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी। पुलिस ने इस कार्रवाई को लेकर प्रेस रिलीज भी जारी की। इसमें एक किशोर की उम्र 18 साल दर्ज की गई और उसे वयस्क आरोपियों के साथ सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

परिजनों ने दूसरी कक्षा की मार्कशीट, आधार कार्ड और बाल न्यायालय की रसीद दिखाते हुए किशोर की उम्र 15 से 16 साल होने का दावा किया है। उनका आरोप है कि पुलिस ने उम्र गलत दर्ज करने के साथ उसकी पहचान भी सार्वजनिक कर दी। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के तहत कानून से संघर्षरत बच्चे की पहचान उजागर करना प्रतिबंधित है। ऐसे में पुलिस की प्रेस रिलीज में नाम, पता और तस्वीर जारी किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं।

प्रशिक्षु एसआई ने बताई उम्र दर्ज करने की वजह

इस मामले में कार्रवाई प्रशिक्षु एसआई लखेश्वर यादव ने की थी। मामला समने आने के बाद अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि किशोर के परिजनों ने नोटिस पर साइन किए थे, लेकिन मौके पर जन्मतिथि से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिया गया था। युवक से पूछने पर उसने अपनी जन्मतिथि 8 नवंबर 2008 बताई थी। इसी आधार पर उसकी उम्र 18 साल 4 दिन दर्ज कर कार्रवाई की गई।

इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि परिजनों के मुताबिक, संबंधित किशोर के खिलाफ करीब एक महीने पहले भी कार्रवाई हुई थी। उस समय बाल न्यायालय ने उसकी उम्र 15 साल मानते हुए 1500 रुपए जुर्माने पर उसे रिहा किया था। परिजनों का कहना है कि बाल न्यायालय की कार्रवाई से जुड़ा रिकॉर्ड होने के बावजूद पुलिस ने उसे वयस्क मानकर जेल भेज दिया।

पुलिस ने अपनी सफाई में कहा है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई उस समय उपलब्ध जानकारी और तथ्यों के आधार पर की गई थी। वास्तविक उम्र के संबंध में प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर उनका परीक्षण कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

परिजनों का आरोप- बिना अपराध बताए मां से कराए हस्ताक्षर

खमतराई अशोक नगर निवासी किशोर के भाई ने बताया कि पुलिस उनके 15-16 साल के छोटे भाई को घर से ले गई और शाम को इसकी सूचना दी। परिजन थाने पहुंचे तो उन्हें बाल न्यायालय जाने के लिए कहा गया। वहां पहुंचने पर पता चला कि भाई की उम्र 18 से 20 साल दर्ज कर उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।

भाई का आरोप है कि पुलिस ने उनकी मां से बिना अपराध बताए कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए। परिजनों के मुताबिक, थाने में इसे लूट का मामला बताया गया, जबकि कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ वकील और बिचौलिए इसे एक्सीडेंट का मामला बता रहे थे। भाई ने यह भी आरोप लगाया कि सेंट्रल जेल से प्रकरण वापस बाल न्यायालय में भेजने के नाम पर कुछ वकीलों ने उनसे 4 हजार रुपए मांगे।

सीएसपी बोले- दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी

सरकंडा सीएसपी तिलेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में उम्र के साक्ष्य से जुड़े दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाते। पुलिस के पूछने पर किशोर ने अपनी जन्मतिथि 8 नवंबर 2008 बताई थी। इसके आधार पर उसकी उम्र 18 साल 4 दिन पाई गई और कार्रवाई की गई। अब परिजन उम्र को लेकर अलग दावा कर रहे हैं। उनके द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी।

पटाखे खरीदने आए युवक को घेरकर पीटा
पल्सर बाइक लूटी, तीन आरोपी गिरफ्तार



श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में पटाखे और घरेलू सामान खरीदने निकले युवक को रास्ते में घेरकर 3 युवकों ने पहले मारपीट की, फिर उसकी पल्सर बाइक लूटकर फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई इस वारदात की शिकायत मिलते ही कोटा पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के चंद घंटों के भीतर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से लूटी गई पल्सर बाइक के साथ वारदात में इस्तेमाल बिना नंबर की स्कूटी भी बरामद की गई है।

एएसपी मधुलिका सिंह ने बताया कि, तखतपुर क्षेत्र के ग्राम समडील निवासी दुर्गेश साहू 10 नवंबर को घरेलू सामान और पटाखे खरीदने के लिए अपनी पल्सर बाइक (सीजी 12 बीएल 1353) से गनियारी आया था। वह सामान लेकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में तीन युवकों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने उससे रुपए मांगे। दुर्गेश ने विरोध किया तो तीनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बदमाश युवकों ने उसकी बाइक लूट ली और फरार हो गए। इस घटना से घबराए दुर्गेश ने कोटा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

मंगला के तीन युवकों ने दिया था वारदात को अंजाम

लूट की सूचना मिलते ही कोटा पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि मंगला के आजाद चौक निवासी अभय सूर्यवंशी (19), नंद कुमार केवट (19) और नीरज सूर्यवंशी (19) इस वारदात में शामिल थे। इस पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उनके कब्जे से लूटी गई पल्सर बाइक और वारदात में इस्तेमाल बिना नंबर की सुजुकी एक्सेस स्कूटी जब्त की गई।

सिविल लाइन क्षेत्र में चोरी की वारदात में भी नाम

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार तीनों युवकों का सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई चोरी की एक वारदात में भी नाम सामने आया है। पुलिस उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य घटनाओं में संभावित संलिप्तता की जांच कर रही है।

चिटफंड कंपनी में कमाई का लालच देकर 24 लाख ठग

लोगों से कराया इन्वेस्टमेंट, 6 साल में दोगुना रकम देने का झांसा, चार डायरेक्टर गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज



बिलासपुर। बिलासपुर में कम समय में दोगुना कमाई का लालच देकर चिटफंड कंपनी के चार डायरेक्टर ने लोगों से 24 लाख रुपए ठग लिए। इसके बाद ऑफिस बंद कर सभी फरार हो गए। पुलिस ने 13 साल पहले कंपनी खोलकर लोगों से ठगी करने वाले चिटफंड कंपनी के चारों डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है।

सीपत के तीरथ राम रात्रे ने मोपका चौकी में ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 2012-13 में ताराचंद पाटले, बसंत यादव, डेरहा कांत और रतन कुर्रे ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रीवेल फूड प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड नाम से चिटफंड कंपनी शुरू की थी। आरोपियों ने आसपास के गांवों के लोगों को 6 साल में पैसा दोगुना करने का लालच दिया। उनके झांसे में आकर तीरथ राम और उनके परिचितों ने कंपनी में करीब 24 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर दिए।

इन्वेस्टमेंट का दिया लालच, पैसे लेकर हो गए फरार

इस दौरान कंपनी के डायरेक्टर और कर्मचारियों ने सरकंडा इलाके में ऑफिस खोल रखा था। उन्होंने लोगों से लाखों रुपए जमा कराए। इसके बदले उनसे फॉर्म भरवाए और बॉन्ड पेपर दिए। साथ ही वादा किया कि 6 साल बाद लोग अपनी जमा रकम निकाल सकेंगे। लेकिन पैसे लेने के बाद कंपनी के डायरेक्टर और कर्मचारी ऑफिस में ताला लगाकर फरार हो गए।

पुलिस ने केस दर्ज कर चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टरों को बुलाकर पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने ठगी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में कुटीपारा मोपका के डेरहा प्रसाद कांत (58), पामगढ़ निवासी ताराचंद पाटले (56), रतन लाल कुर्रे (55) और खरौद निवासी बसंत यादव (70) को गिरफ्तार किया है। चारों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

आरोपियों से बांड पेपर और पासबुक जब्त

जांच के दौरान पुलिस ने चिटफंड कंपनी के दस्तावेज, लोगों से जमा कराए गए बॉन्ड पेपर और पासबुक समेत कई सामान बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने निवेश के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों से पैसे जमा कराए थे। इस मामले में पुलिस एक दर्जन से ज्यादा अन्य पीड़ितों से भी शिकायत लेने की तैयारी कर रही है। उनकी शिकायतों को भी इसी केस की जांच में शामिल किया जाएगा।

केशकाल घाट में ओवरटेकिंग को लेकर विवाद, तलवार से हमला करने वाला गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज



केशकाल। केशकाल घाट क्षेत्र में यातायात नियमों की अनदेखी कर गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना एक वाहन चालक को भारी पड़ गया। ओवरटेकिंग को लेकर हुए विवाद में दूसरे ट्रेलर चालक के साथ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने और तलवार से हमला करने के मामले में केशकाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

ओवरटेकिंग को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि ट्रेलर चालक विक्रम सिंह ने तारसेन सिंह एवं उनके साले हिरासिंह के साथ अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने अपने ट्रेलर वाहन से धारदार तलवार निकालकर दोनों पर हमला कर दिया।

मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर केशकाल पुलिस ने आरोपी विक्रम सिंह पिता बख्शीस सिंह, निवासी अर्जुन नगर सुपेला, जिला दुर्ग के विरुद्ध थाना केशकाल में अपराध क्रमांक 187/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 351(3) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका

उक्त कार्रवाई में निरीक्षक रितेश मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक सुरेश मरकाम एवं हेमंत देवांगन, प्रशिक्षु उप निरीक्षक राखी यादव, प्रधान आरक्षक ईश्वर नेताम एवं विनय बघेल, महिला प्रधान आरक्षक बिमला मण्डावी सहित आरक्षक धर्मेंद्र नेगी, मनोहर निषाद, सदासिंह नेताम, लिलेश्वर ध्रुव, महिला आरक्षक सुमन आयाम, सोनल यादव एवं गोपनीय सैनिक अनिल कुलदीप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कमीशन के लालच में बैंक खाते बेचकर ठगी की रकम खपाने वाले 14 आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज



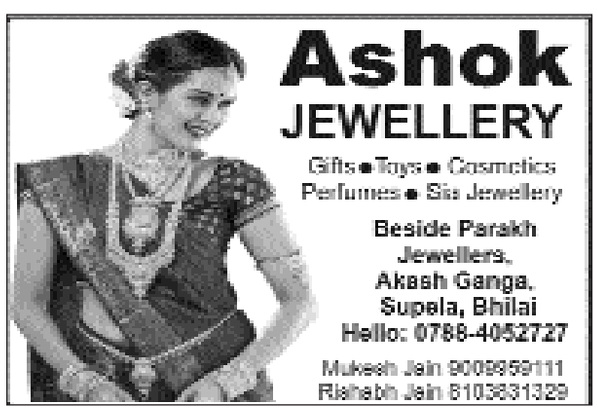
भिलाई। दुर्ग में साइबर ठगी की रकम खपाने के लिए म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने के मामले में पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 14 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार जामुल और पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र तथा एसीसीयू की संयुक्त कार्रवाई में यह गिरफ्तारी हुई। थाना पद्मनाभपुर में 2 एजेंट भी पकड़े गए हैं।

जांच में सामने आया कि आरोपी कमीशन के लालच में अपने और अन्य लोगों के बैंक खाते साइबर अपराधियों को देते थे, जिनके जरिए ठगी की राशि का लेन-देन और स्थानांतरण किया जाता था। पुलिस के अनुसार पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और पंजीकृत मोबाइल सिम 5,000 से 15,000 रुपए तक लेकर उपलब्ध कराए जाते थे। दो अलग प्रकरणों में वैधानिक कार्रवाई की गई है। आरोपियों के कब्जे से पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए।

आरोपियों में सेक्टर-7, एवन्यू ए निवासी मनोज यादव, पैराडाइस कॉलोनी, बोरसी निवासी प्रदीप कुमार, चौहान टाउन, सुपेला निवासी अक्षय राज, गौतम नगर सुपेला निवासी महेश महानंद, उपेन्द्र सिंह, वार्ड 18, कैंप-1, सुपेला निवासी संतोष कुमार सोनी, शास्त्री नगर, कैंप-1 निवासी कुंदन कुमार, श्रीनिवास शक्ति विहार, रिसाली निवासी सुमित कुमार सिंह, घासीदास नगर, जामुल निवासी लोकेश बघेल, न्यू संतोषी पारा छावनी निवासी मोहन मांझी, कैंप-1, जलेबी चौक निवासी अंकित डोंगरे, रायपुर नाका दुर्ग निवासी आशुतोष तांडी, तलवार बिल्डिंग के पास, सुभाष नगर दुर्ग निवासी हेमा सिन्हा, सेक्टर-6 निवासी सरस्वती ठाकुर शामिल हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी को अपना बैंक खाता या बैंकिंग दस्तावेज उपयोग के लिए न दें और संदेह होने पर हेल्पलाइन 1930 या पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत करें।

शिकार से पहले वन विभाग ने दबोचे 4 आरोपी

जगदलपुर। जगदलपुर के जंगलों में वन्यजीवों के शिकार के लिए बिजली के तारों का इस्तेमाल करने की तैयारी थी, लेकिन वन विभाग की सतर्कता ने आरोपियों की योजना नाकाम कर दी। दरभा वन परिक्षेत्र और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की संयुक्त टीम रात्रिकालीन गश्त पर निकली थी। 12 और 13 नवंबर की दरम्यानी रात आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1425 में टीम को संदिग्ध गतिविधियां नजर आईं। जंगल के भीतर चार व्यक्ति बिजली के तारों का फंदा बिछाते हुए मिले। पूछताछ में सामने आया कि जंगली सुअर के शिकार की तैयारी की जा रही थी। वन विभाग की टीम ने मौके पर ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अपराध दर्ज किया गया।







खास खबर



महतारी वंदन से सीमा की गृहस्थी को मिला सहारा

रायगढ़। महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता का आधार बन रही है। जिले के ग्राम ननसिया की रहने वाली सीमा चौहान के लिए भी यह योजना काफी मददगार साबित हो रही है। सीमा ने बताया कि हर महीने मिलने वाली राशि से घर के जरूरी सामान और बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। दीपावली त्योहार से पहले खाते में मिली राशि से घर की पुताई कराई और बच्चों के लिए मिठाइयां व पूजा की सामग्री खरीदी।

बलौदाबाजार में ग्राम सभा का आयोजन 16 नवम्बर को

बलौदाबाजार। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों में 16 नवम्बर को ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने ग्राम सभा हेतु समय-सारिणी तैयार कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। ग्राम सभा में शतप्रतिशत गणपूर्ति सुनिश्चित कराने का दायित्व सरपंच व पंचो का होगा।

विधान सभा का ग्यारहवां सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक

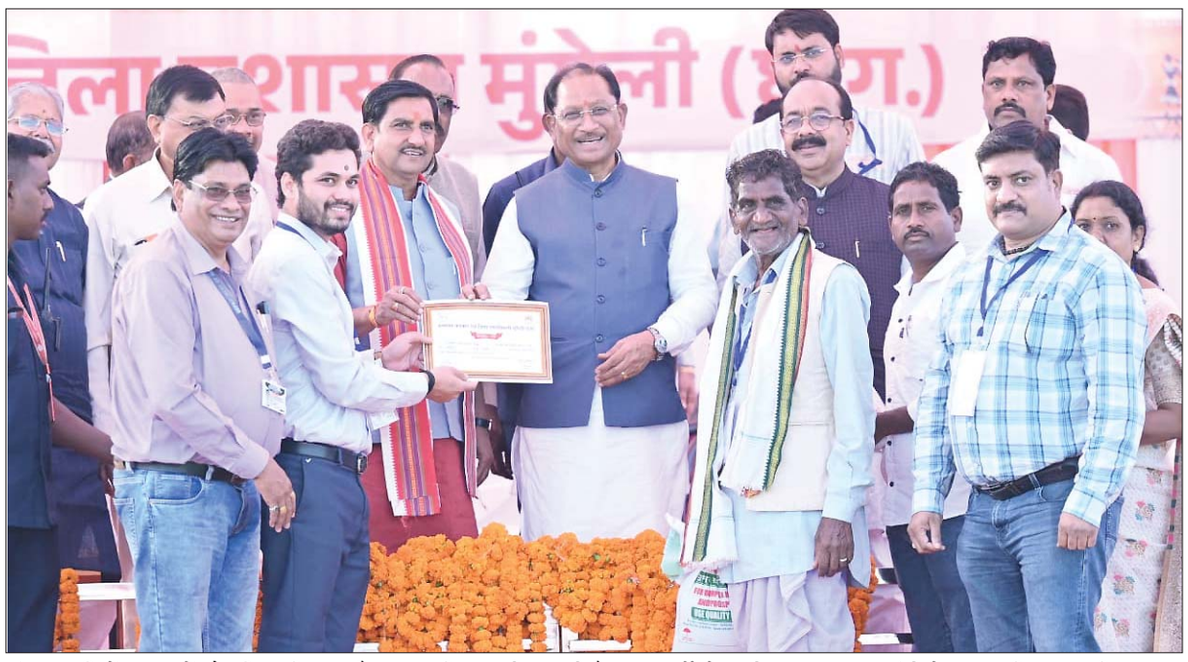
कोरबा। छत्तीसगढ़ की पष्ठम् विधान सभा का ग्यारहवां सत्र सोमवार 14 दिसंबर 2026 से प्रारंभ होकर गुरूवार 17 दिसंबर 2026 तक रहेगा। विधानसभा प्रश्नों का उत्तर निर्धारित समयावधि में शासन/वरिष्ठ कार्यालय की ओर भेजा जाना आवश्यक होता है। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आदेश जारी कर सभी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी आज दिनांक 13 नवंबर 2026 से 17 दिसंबर 2026 तक कलेक्टर के अनुमति के बिना मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे।

गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं-बहनों और युवाओं का सर्वांगीण विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : साय

● कल शुरू होगी धान खरीदी, 3100 की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक होगी खरीदी ● आदान सहायता का भुगतान प्रति एकड़

- 13,839 रुपए प्रति एकड़ की दर से मिलेगी आदान सहायता
- विकसित भारत को साकार करने में छत्तीसगढ़ निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका
- मुंगेली जिले को दी 465 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात
- कंतेली में महाविद्यालय भवन और पंचायत भवन सहित विभिन्न कार्यों की घोषणा
- सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को मिलेगा विस्तार

श्रीकंचनपथ समाचार



मुंगेली। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जिलेवासियों को 46540 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 77 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 24 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 397 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 53 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया।

इन कार्यों से जिले में सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की खुशहाली, किसानों की समृद्धि और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना राज्य सरकार का प्रमुख संकल्प है। विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब वहां के गांव मजबूत हों, किसानों को बेहतर संसाधन मिलें, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ें तथा आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हों। मुंगेली जिले में आज जिन विकास कार्यों की सौगात दी गई है, वे इसी सोच को धरातल पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुंगेली जिले में अधोसंरचना विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इन कार्यों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होगा तथा किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। अच्छी सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों का रास्ता भी खोलती हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों को बेहतर जल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इन कार्यों से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सिंचाई संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम होगी और उन्हें खरीफ के साथ रबी एवं अन्य फसलों की खेती के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इससे फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने ग्राम कंतेली में महाविद्यालय भवन एवं पंचायत भवन के निर्माण, ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका के निर्माण तथा ग्राम कोदवा से खुर्शी तक सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम है। कंतेली में महाविद्यालय भवन के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण अंचलों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका का निर्माण हमारी भावी पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के त्याग, बलिदान और राष्ट्रसेवा से प्रेरणा देगा।

किसानों की समृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध, 15 नवंबर से धान खरीदी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर लगभग 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सुगम और किसान हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें निर्धारित समय पर भुगतान प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सहायता राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को धान की निर्धारित पूरी मात्रा का विक्रय करना अनिवार्य नहीं होगा। यदि कोई किसान निर्धारित मात्रा से कम धान का विक्रय करता है, तब भी उसे सत्यापित रकबे के आधार पर निर्धारित पात्रता के अनुसार आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों को खेती के लिए आर्थिक संबल मिले और वे अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार कृषि संबंधी निर्णय ले सकें।

महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा आर्थिक संबल

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 68 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 33 किस्तों में 21 हजार 340 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है।

श्रीरामलला दर्शन योजना से पूरी हो रही वरिष्ठजनों की आस्था

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि माता कौशल्या की यह पावन धरती छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल है। प्रदेशवासियों की आस्था का सम्मान करते हुए सरकार श्रीरामलला दर्शन योजना का संचालन कर रही है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से समस्याओं का त्वरित समाधान

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर की गई शिकायतों से समस्याओं का तत्काल समाधान हो रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याएं और शिकायतें हेल्पलाइन नंबर 1076 पर दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

छत्तीसगढ़ में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन इसके अनुसार में प्रदेश में वर्तमान में 1.90 करोड़ मतदाता

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में चलाए जा रहे निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027) के तहत 12 नवम्बर को सभी मतदान केन्द्रों में निर्वाचन नामावली का प्रारूप (ड्राफ्ट) सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप सूची की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। ईसीआई नेट मोबाइल एप्प एवं वोटर पोर्टल पर भी मतदान केन्द्रवार निर्वाचक नामावली की प्रारूप सूची ऑनलाइन प्रकाशित कर दी गई है।

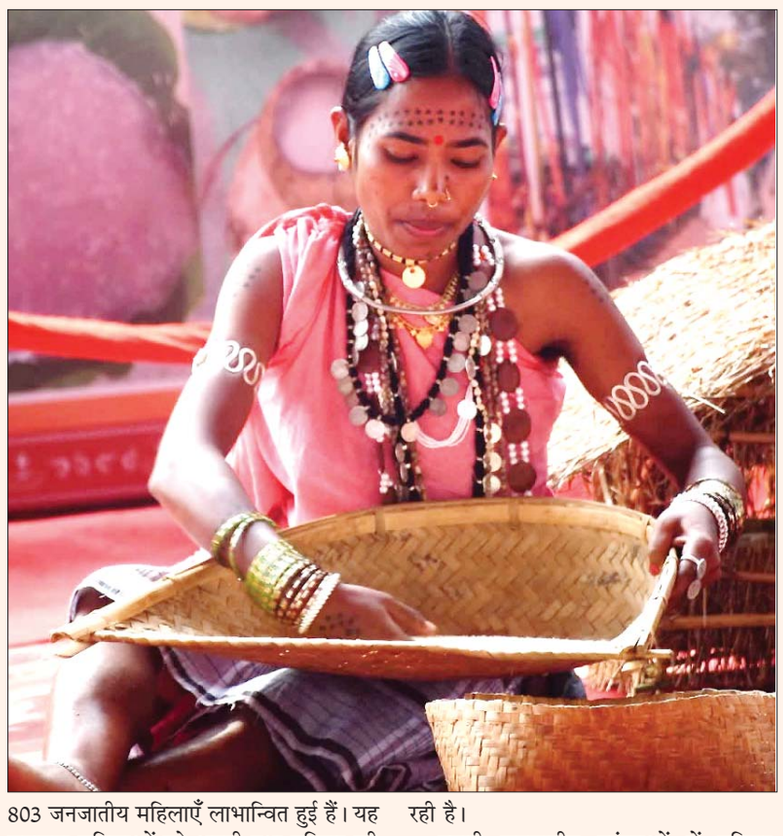
छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने बताया कि 12 नवम्बर को प्रकाशित निर्वाचक नामावली की प्रारूप सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1,90,16,768 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 94,86,635 पुरूष, 95,31,721 महिला और 412 थर्ड जेंडर सम्मिलित हैं। युक्तियुक्तकरण 02 नवम्बर 2026 के पूर्व प्रदेश में मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 27196 थी, युक्तियुक्तकरण में 47 नए मतदान केन्द्र स्थापित किए गए तथा 389 मतदान केन्द्रों का विलोपन किया गया। इस प्रकार प्रदेश में अब मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 26,854 है, जिनमें 5876 शहरी और 20978 केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

ऐसे चेक करें अपना नाम-

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अपील की है कि मतदाता निर्वाचक नामावली की ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जरूर चेक करें। इसके लिए ईसीआईनेट मोबाइल एप के माध्यम से चेक किया जा सकता है। वोटर पोर्टल www.voters.eci.gov.in के जरिए या अपने नजदीकी मतदान केन्द्र के बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन चेक भी कराया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी कॉल किया जा सकता है। यदि निर्वाचक नामावली की प्रारूप सूची में किसी मतदाता का नाम सम्मिलित नहीं है या विवरण त्रुटिपूर्ण दर्ज है अथवा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल हो गया है तो ईसीआईनेट मोबाइल एप या वोटर पार्टल www.voters.eci.gov.in के माध्यम से फॉर्म-6 नए मतदाता पंजीकरण के लिए, फॉर्म-6(क) एनआरआई के नए पंजीकरण हेतु, फॉर्म-7 निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित (डिलीट) कराने तथा फॉर्म-8 प्रविष्टि में संशोधन/स्थानांतरण/नया इपिक कार्ड या स्वयं को दिव्यांग मतदाता के रूप में चिन्हांकित कराने के लिए भरा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय महिलाओं और बेटियों के सम्मान, प्रतिभा और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन

डॉ. दानेश्वरी संभाकर



रायपुर। जनजातीय गौरव दिवस हमें अपनी समृद्ध विरासत और उन जननायकों के अदम्य साहस को स्मरण करने का अवसर देता है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता, समाज सुधार और जनकल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह, वीर गुण्डाधुर और रानी दुर्गावती का संघर्ष, स्वाभिमान और त्याग हमारी साझा धरोहर है। उनके जीवन से हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, अपनी संस्कृति पर गर्व करने और समाज के हर वर्ग को सम्मान देने की प्रेरणा मिलती है।

जनजातीय समाज की महिलाएँ अपनी परंपराओं, परिवारों और समुदायों की मजबूत आधारशिला रही हैं। आज वे शिक्षा, खेल, कला, आजीविका और नेतृत्व सहित अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। कोंडागांव जिले के बालिका गृह की दो जनजातीय बालिकाओं को पिछले दो वर्षों में खेलों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना इस प्रतिभा और संकल्प का प्रेरक उदाहरण है। उनकी उपलब्धि बताती है कि उचित अवसर, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिले तो बेटियाँ किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं और जनजातीय परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में महतारी वंदन योजना से 20 लाख 28 हजार 803 जनजातीय महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं। यह सहायता महिलाओं को अपनी तथा परिवार की जरूरतों के लिए निर्णय लेने में संबल देती है और उनकी आर्थिक भागीदारी को मजबूत करती है।



परिवारों के जीवन में बेटियों का विवाह एक महत्वपूर्ण और आनंद का अवसर होता है। आर्थिक कठिनाइयाँ इस अवसर पर परिवारों के लिए चिंता का कारण न बनें, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को सहयोग दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से 2,072 विवाह सम्पन्न हुए हैं, जिनमें लगभग 580 हितग्राही अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। यह पहल बेटियों के विवाह को गरिमा और सम्मान के साथ सम्पन्न कराने में परिवारों का सहारा बन रही है।

हमारी जनजातीय परंपराओं में परिवार, समुदाय और परस्पर सहयोग का विशेष महत्व है। शासन की योजनाओं का उद्देश्य भी यही है कि सहायता जरूरतमंद लोगों तक पहुँचे और उनके जीवन में वास्तविक संबल बने। महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और आजीविका से जुड़े प्रयासों के साथ परिवारों को सामाजिक अवसरों पर सहयोग देना समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

जनजातीय गौरव दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि अपनी गौरवशाली विरासत और जननायकों के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुँचाएँगे। जनजातीय समाज की बेटियों को शिक्षा, खेल, कौशल और रोजगार के अवसरों से जोड़ना तथा उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना परिवार, समाज और शासन सभी की साझा जिम्मेदारी है।

विश्वास है कि जब बेटियाँ आत्मविश्वास और सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगी, तो उनका योगदान पूरे समाज को नई दिशा देगा। जनजातीय गौरव का सच्चा सम्मान इसी में है कि हर बेटी को अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर मिले और वह अपने परिवार तथा प्रदेश की प्रगति में भागीदार बने।

(उप संचालक, छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क)

बाल संरक्षण की दिशा में छत्तीसगढ़ की अभिनव पहल, स्कूलों में गठित करेंगे 'बाल प्रहरी क्लब'

श्रीकंचनपथ समाचार



रायपुर। बाल अधिकारों की रक्षा और विद्यालयों में सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में 'बाल प्रहरी क्लब' गठित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ने प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय हाई स्कूलों तथा हायर सेकेंडरी विद्यालयों में इन क्लबों के गठन एवं संचालन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त श्री इंद्रजीत सिंह खालसा की उपस्थिति में एमओयू संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोग के सचिव श्री बृजेंद्र सिंह सहित दोनों संस्थाओं के अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस पहल के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ अपने सहपाठियों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार बनाया जाएगा। क्लब बाल विवाह, बाल श्रम, नशे, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी जैसी समस्याओं तथा अधिकारों के उल्लंघन की आशंका के बारे में समय रहते संबंधित संस्थाओं तक सूचना पहुंचाने में मदद करेंगे। लगातार अनुपस्थित रहने वाले या संकटग्रस्त बच्चों की पहचान कर उन्हें परामर्श और सहयोग के जरिए शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखने का प्रयास भी किया जाएगा।

प्रत्येक क्लब दस विषयों पर काम करेगा। इनमें बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता तथा साइबर सुरक्षा एवं मानव तस्करी की रोकथाम पांच स्थायी विषय होंगे। शेष पांच विषय स्थानीय जरूरतों के अनुसार चुने जाएंगे। इनमें आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा, पलायन की निगरानी, स्ट्रीट चिल्ड्रन का पुनर्वास, किशोर स्वास्थ्य और अंधविश्वास उन्मूलन जैसे विषय शामिल हो सकते हैं।

क्लबों को ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 से समन्वित किया जाएगा। क्लब नियमित जागरूकता गतिविधियां और मासिक प्रगति प्रतिवेदन संचालित करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को 'श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान' से प्रोत्साहित किया जाएगा।

बाल प्रहरी के रूप में चुने गए विद्यार्थियों की भूमिका जागरूकता, सूचना और सहयोग तक सीमित रहेगी। बच्चों की सुरक्षा और पहचान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 23, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 और भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने इस पहल को बाल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नवाचार बताया।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950